

ज्वाला एक्सप्रेस न्यूज



आर.एन.आई. नं. :- CHHHIN/2021/82386

सच्ची खबर सबसे पहले

online- jwalaexpress.com

वर्ष - 05, अंक -15

दुर्ग (छ.ग.), दिनांक 11 दिसंबर से 17 दिसंबर 2025 (प्रत्येक गुरुवार)

पृष्ठ - 8, मूल्य - 05 रुपए

छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने प्रदेश के 6 विश्वविद्यालयों के साथ किया एमओयू

रक्षक पाठ्यक्रम छात्रों के सुरक्षित भविष्य गढ़ने में सहायक होगा - मुख्यमंत्री साय



देश का पहला पाठ्यक्रम छात्रों को मिलेगी बाल अधिकार एवं संरक्षण की जानकारी

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की उपस्थिति में राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग एवं प्रदेश के छह विश्वविद्यालयों के मध्य रक्षक पाठ्यक्रम के लिए एमओयू संपन्न हुआ। बाल अधिकार एवं संरक्षण पर आधारित यह अनूठा पाठ्यक्रम देश

में अपनी तरह का पहला शैक्षणिक नवाचार है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि रक्षक पाठ्यक्रम छात्रों के सुरक्षित और जिम्मेदार भविष्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि यह पाठ्यक्रम युवाओं को न केवल रोजगार के अवसर प्रदान करेगा, बल्कि बाल अधिकार संरक्षण के क्षेत्र में आवश्यक विशेषज्ञता भी विकसित करेगा। उन्होंने कहा कि कई बार बच्चे भूलवश या भ्रमित होकर गलत दिशा में चले जाते हैं क्योंकि वे अवोध होते हैं। ऐसे

बच्चों को सही मार्ग पर लाना हम सभी का सामूहिक दायित्व है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि पिछले दो वर्षों में राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी के अधिकांश वादों को पूरा कर लिया है। किसानों के बकाया बोनस, महिलाओं के लिए महतारी वंदन योजना और सबके लिए आवास जैसे महत्वपूर्ण संकल्पों को साकार किया गया है। उन्होंने कहा कि 350 से अधिक प्रशासनिक सुधार लागू कर छत्तीसगढ़ सुशासन के मार्ग पर तेजी से अग्रसर

है और इसी उद्देश्य से सुशासन एवं अभिसरण विभाग की स्थापना भी की गई है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने रक्षक पाठ्यक्रम को रिकॉर्ड समय में तैयार करने और विश्वविद्यालयों में इसे लागू करने के लिए आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा और उनकी पूरी टीम को बधाई दी। महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी रजवाड़े ने कहा कि बाल अधिकार संरक्षण के क्षेत्र में व्यापक प्रयासों की आवश्यकता है। बच्चों से भिक्षावृत्ति कराना, परित्यक्त बच्चों का पुनर्वास, और संवेदनशील मामलों का समाधान—ये सभी अत्यंत चुनौतीपूर्ण विषय हैं। उन्होंने कहा कि यह पाठ्यक्रम संवेदनशील, सजग और सेवा-भावयुक्त युवा तैयार करने में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने इसे राष्ट्रीय स्तर का नवाचार बताते हुए कहा कि भविष्य में छत्तीसगढ़ इस क्षेत्र में अग्रणी राज्य के रूप में पहचाना जाएगा। उच्च शिक्षा मंत्री श्री ठाकुर राम वर्मा ने पाठ्यक्रम को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह छत्तीसगढ़ के लिए गौरव का विषय है। उन्होंने आयोग और सभी छह विश्वविद्यालयों को पाठ्यक्रम लागू करने हेतु बधाई दी।

यह एक वर्षीय स्नातकोत्तर पीजी डिप्लोमा इन चाइल्ड राइट्स एंड प्रोटेक्शन

पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर, संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा, कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर, आर्जनेय विश्वविद्यालय, रायपुर, एमिटी विश्वविद्यालय, रायपुर और श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, भिलाई-दुर्ग में प्रारम्भ होगा।

वया है रक्षक पाठ्यक्रम

प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय में अब तक ऐसा पाठ्यक्रम उपलब्ध नहीं था, जो युवाओं को बाल अधिकार संरक्षण के क्षेत्र में प्रशिक्षित करते हुए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए। इस आवश्यकता को देखते हुए आयोग द्वारा फ़ररक्षक ङ्क बाल अधिकार संरक्षण पर एक वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमका को विकसित किया गया है। इस पाठ्यक्रम से युवाओं को सैद्धांतिक एवं विधिक ज्ञान, विभागीय योजनाओं, संस्थाओं और प्रायोगिक प्रक्रियाओं की गहरी समझ, बाल संरक्षण इकाइयों आदि के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध होगी। संवेदनशीलता, जागरूकता और बाल-अधिकारों की आत्मिक समझ विकसित करने वाला यह पाठ्यक्रम युवाओं को इस क्षेत्र में कुशल, समर्पित और प्रभावी मानव संसाधन के रूप में तैयार करेगा। आयोग द्वारा पाठ्यक्रम के संचालन, प्रशिक्षण, परामर्श और मार्गदर्शन की संपूर्ण सुविधा विश्वविद्यालयों को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी।

कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर से कुलसचिव प्रो शैलेन्द्र पटेल, प्रो ए के श्रीवास्तव, संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय सरगुजा कुलपति प्रो राजेंद्र लाकपाले, कुलसचिव श्री शारदा प्रसाद पिपाडी, कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय रायपुर के कुलपति एवं रायपुर सभाग आयुक्त श्री महादेव कावरे, कुलसचिव श्री सुनील कुमार शर्मा, आर्जनेय विश्वविद्यालय रायपुर कुलपति डॉ. टी. रामाराव कुलसचिव डॉ. रूपाती चौधरी, एमिटी विश्वविद्यालय रायपुर कुलपति डॉ. पीयूष कांत पाण्डेय, कुलसचिव डॉ. सुरेश ध्यानी, श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी भिलाई दुर्ग चांसलर डॉ.आई.पी. मिश्रा, कुलपति डॉ ए. के झा एवं डॉ जया मिश्रा, आयोग के सचिव प्रतीक खरे सहित अन्य विभागीय अधिकारीगण उपस्थित थे।

तांदुला संभागीय कार्यालय एवं उपसंभागीय भवनों का लोकार्पण

स्कूल शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव ने किया उद्घाटन

दुर्ग। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव ने जल संसाधन विभाग दुर्ग के तांदुला संभागीय कार्यालय एवं उपसंभागीय भवनों का लोकार्पण पीता काटकर किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अहिंवारा विधायक ललित चंद्राकर, तेलघानी विकास बोर्ड अध्यक्ष जितेन्द्र कुमार साहू, अधीक्षण अभियंता सुरेश कुमार पांडेय एवं कार्यपालन अभियंता आशुतोष सारस्वत सहित विभागीय अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

इस अवसर पर स्कूल शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव ने इस भवन को प्रदेश में जल संसाधन प्रबंधन और कृषक हितों के क्षेत्र में उच्च दक्षता, पारदर्शिता और तकनीकी प्रगति का उत्कृष्ट उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि यह आधुनिक परिसर पुराने जर्जर भवन की जगह, भविष्यदृष्टा और टिकाऊ तकनीकी मानकों के अनुसार विकसित



किया गया है, जिससे विभागीय कार्य प्रणाली और जनता-केंद्रित सेवाओं में स्पष्ट रूप से सुधार आएगा। वर्ष 1912 में निर्मित पुराना भवन समय के साथ अत्यधिक जर्जर हो गया था, जिससे विभागीय कार्य प्रणाली और आम जनता को अपेक्षित सुविधा प्रभावित हो रही थी। भवन का पुनर्निर्माण दूरगामी दृष्टि, भवन की जगह, भविष्यदृष्टा और टिकाऊ तकनीकी मानकों और जनता-केंद्रित प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुरूप

किया गया। इस परियोजना की कुल लागत रु. 336.67 लाख है। यह परिसर दुर्ग जिले में 1.27 लाख हेक्टेयर कृषि क्षेत्र की सिंचाई योजनाओं, जल संरक्षण एवं अनुरक्षण कार्य और डिजिटाइज्ड अभिलेख प्रणाली के संचालन में केंद्रीय भूमिका निभाएगा। उन्होंने सिंचाई के लिए नहर को पुनर्वसन द्वारा प्रवृत्त जल सिधे बिछने से सभी प्रकार के वाटर रिसोर्स रिचार्ज किया जा सकता है।

नवीन भवन में अत्याधुनिक तकनीकी सुविधाएं सम्मिलित हैं, संरचना के साथ दीर्घकालिक स्थायित्व, फ्लाइ ऐश ब्रिक आधारित पर्यावरण-सम्मत निर्माण, प्राकृतिक वेंटिलेशन और पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था, ऊर्जा-दक्ष प्रकाश एवं वातानुकूलन प्रणाली, सुरक्षित अभिलेख कक्ष और डिजिटाइज्ड ई-ऑफिस अवसंरचना, बहुउद्देश्यीय बैठक कक्ष, विस्तारित कॉरिडोर और सुरक्षित आगंतुक मार्ग, तथा भविष्य की वृद्धि के अनुरूप अनुकूलनीय रूपरेखा। इन सभी तकनीकी पहलुओं ने भवन को प्रशासनिक उत्कृष्टता, कार्यकुशलता और पर्यावरणीय संतुलन का आदर्श केंद्र बनाया।

प्रदेश के अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष एवं अहिंवारा विधायक डोमनलाल कासेवाड़ा ने भी जल संरक्षण पर अपने विचार रखते हुए कहा कि सभी जलाशयों में गहरीकरण और सौंदर्यीकरण की जरूरत है। उन्होंने कहा कि चर्चानियों द्वारा प्रवृत्त जल सिधे जलाशयों में छोड़ा जा रहा है। इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि

जलाशयों की शुद्धता और पर्यावरण संतुलन बनाए रखा जा सके। कार्यक्रम के दौरान छ.ग.राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष एवं दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर ने कहा कि नए संभाग के गठन के साथ जिले के विकास की संभावनाएं और बढ़ गई हैं। बदलते समय के साथ स्वयं को अपडेट करना और निरंतर नवाचार करना आवश्यक है। उन्होंने जल के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि पाँच तत्वों में जल का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है और भारत जैसे कृषि प्रधान देश में पानी का संरक्षण अत्यावश्यक है। आधुनिक तकनीक की मदद से पानी के उपयोग को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि जिले में व्यापक स्तर पर सोखता निर्माण का कार्य जारी है। इसी पहल के लिए जिले को हाल ही में विशेष पुरस्कार भी मिला है। उन्होंने कहा कि यदि प्रत्येक परिवार अपने घरों में खिकता का निर्माण करे, तो जल संकट को काफी हद तक दूर किया जा सकता है।

नारी सम्मान और सशक्तीकरण के लिहाज से भाजपा सरकार के दो वर्ष का कार्यकाल ऐतिहासिक - शताब्दी

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता शताब्दी पाण्डेय ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश की भाजपा सरकार के दो वर्षों के कार्यकाल को नारी सम्मान की रक्षा और राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक सशक्तीकरण के लिहाज से ऐतिहासिक बताया है। श्रीमती पाण्डेय ने प्रदेश की भाजपा सरकार के दो वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियों की चर्चा करते हुए कहा कि हर क्षेत्र में आज प्रदेश की महिलाएँ विकास की मुख्याधार के केंद्र में हैं।

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता श्रीमती पाण्डेय ने कहा कि भाजपा ने मोदी की गारंटी के तहत महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान व सशक्तीकरण के जो संकल्प व्यक्त किए थे, उन पर तेजी से अमल करके साय-सरकार ने मातृ-शक्ति का अभूतपूर्व विश्वास अर्जित किया है। सत्ता में आने के बाद भाजपा की सरकार ने प्रदेश की विवाहित महिलाओं के लिए महतारी वंदन योजना शुरू की और 10 मार्च, 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्युअल उपस्थिति में महतारी वंदन योजना के अंतर्गत महिलाओं के बैंक खातों में राशि अंतरण का शुभारंभ हुआ।

इस योजना में 70 लाख महिलाओं को प्रति माह एक-एक हजार रुपए की राशि खाते में जमा हो रही है। अब तक महतारी वंदन योजना की 22 किश्तें जारी कर दी गई हैं। श्रीमती पाण्डेय ने कहा कि 179 महतारी सदन के निर्माण के लिए 52 करोड़ 20 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। प्रदेश की मितानिनों को अब हर माह प्रोत्साहन राशि के ऑनलाइन भुगतान की व्यवस्था लागू की गई है। स्व-सहायता समूह के हित को ध्यान में रखते हुए चरणबद्ध तरीके से छह जिलों में पायलेट प्रोजेक्ट के तहत रेडी टू ट्रीट का काम महिला समूहों को सौंपा गया है। श्रीमती पाण्डेय ने कहा कि भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत देशभर में 25 लाख नए एलपीजी कनेक्शन स्वीकृत किए गए हैं।

दीवारें बनीं शिक्षक, बच्चे बने जिज्ञासु : धमतरी का अभिनव बाला मॉडल



खेल-खेल में सीखने की पहल : बाला कॉन्सेप्ट पर आधारित आंगनवाड़ी केंद्रों से बदलती तस्वीर

धमतरी। प्रारंभिक बाल शिक्षा को अधिक प्रभावी, आकर्षक और बच्चों की सहज सीखने की प्रक्रिया के अनुरूप बनाने के उद्देश्य से धमतरी जिले में बाला बिल्डिंग एस लर्निंग ऐंड कॉन्सेप्ट आधारित आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण एक महत्वपूर्ण नवाचार के रूप में उभर रहा है। यह पहल न

केवल शिक्षण-सीखने की गुणवत्ता को बढ़ा रही है, बल्कि बच्चों को एक ऐसे रचनात्मक वातावरण से जोड़ रही है जहाँ वे खेल-खेल में ज्ञान अर्जित कर सकें।

बाला कॉन्सेप्ट का मूल विचार यह है कि भवन स्वयं बच्चों का शिक्षक बन जाए। इस मॉडल में दीवारों, फर्श, खिड़कियों, दरवाजों, सीढ़ियों यहां तक कि बाहरी खुली जगहों को भी सीखने के साधनों के रूप में विकसित किया जाता है। अक्षर, संख्याएँ, रंग, आकार, मौसम, स्थानीय

परिवेश से जुड़े चित्र, दिशासूचक संकेत, ऊँचाई नापने के चार्ट जैसे अनेक तत्व सहज रूप से बच्चों तक ज्ञान पहुंचाते हैं। इससे बच्चों में जिज्ञासा बढ़ती है, स्मरण शक्ति बेहतर होती है और सीखने की प्रक्रिया सक्रिय एवं आनंददायी बन जाती है। इसी अभिनव सोच को मूर्त रूप देते हुए धमतरी जिला प्रशासन ने मनरेगा, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा 15 वें वित्त आयोग के वित्तीय सहयोग से जिले में 81 बाला मॉडल आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण प्रारंभ किया है। इनमें से 38 केंद्र पूर्ण हो चुके हैं, जबकि शेष पर तेजी से कार्य जारी है। हाल ही में कलेक्टर अविनाश मिश्रा ने विकास विभाग धमतरी के ग्राम उड्डेना में निर्मित नवीन आंगनवाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया। लगभग 11.69 लाख रुपये की लागत से तैयार यह भवन न सिर्फ आकर्षक है, बल्कि बाला कॉन्सेप्ट की सभी विशेषताओं को समाहित करते हुए सीखने का आदर्श वातावरण प्रस्तुत करता है। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर संतोष व्यक्त करते हुए शेष कार्य को भी निधारित समयसीमा में बेहतर गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिए।

मतदाता सूची का शुद्धीकरण लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में आवश्यक कदम; सांसद बृजमोहन अग्रवाल

रायपुर। रायपुर लोकसभा सांसद और वरिष्ठ भाजपा नेता श्री बृजमोहन अग्रवाल ने आज एक महत्वपूर्ण बयान जारी करते हुए कहा कि मतदाता सूची का समय-समय पर पुनरीक्षण लोकतांत्रिक व्यवस्था के स्वास्थ्य और पारदर्शिता के लिए अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया से न केवल मतदाता लाभान्वित होते हैं, बल्कि राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले सभी प्रत्याशियों को भी इससे निष्पक्ष एवं विश्वसनीय वातावरण प्राप्त होता है। श्री अग्रवाल ने कहा कि, मतदाता सूची का शुद्धीकरण लोकतंत्र का पवित्रीकरण है। जब मतदाता सूची सही होती है तभी जनतादेश की पवित्रता सुरक्षित रहती है। हम सबको, चाहे मतदाता हों, राजनीतिक दल हों अथवा उम्मीदवार—इस प्रक्रिया को सकारात्मक रूप से सहयोग देना चाहिए। इस मौके पर सांसद अग्रवाल ने विपक्ष के रवैये की आलोचना करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी कई बार जनता के जनादेश को स्वीकार करने में हिचक दिखाती रही है। कांग्रेस



अपनी लगातार हो रही पराजयों को समझने के बजाय अनावश्यक आपत्तियाँ और भ्रम फैलाने में लगी रहती है। लोकतंत्र में जनता सर्वोच्च है, और उसके निर्णय का सम्मान प्रत्येक दल को करना चाहिए। सोनिया गांधी को समन जारी होने पर प्रतिक्रिया दिखी की अदालत द्वारा श्रीमती सोनिया गांधी को उनके वोटर आईडी कार्ड मामले में समन जारी किए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए सांसद अग्रवाल ने कहा कि यह मामला लंबे समय से सार्वजनिक चर्चा में रहा है और अब न्यायालय के हस्तक्षेप से सत्य सामने आने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि, देश में यह शंका वर्षों से उठाई जाती रही है कि क्या सोनिया गांधी का वोटर आईडी कार्ड विधिसम्मत रूप से बना था।

रायगढ़ मेडिकल कॉलेज में मरीजों के लिए न्यूरोसर्जन, यूरो सर्जन एवं नेफ्रोलॉजी डॉक्टर की सुविधा



विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपस्थिति से होगा लाभ, लोगों को मेडिकल कालेज में ही मिलेगी चिकित्सा

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य के सरकारी और सुशासन के सफर में स्वास्थ्य सुविधाओं का भी विस्तार लगातार हो रहा है। इसी दिशा में र्व. श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय से संबद्ध संत बाबा गुरु चासीदास जी स्मृति शासकीय चिकित्सालय रायगढ़ में दिवंगत अधिष्ठाता डॉ.विनीत जैन के द्वारा किए गए प्रयासों के उपरांत शहर के

सुप्रसिद्ध न्यूरोसर्जन डॉ. नितीश नायक ,यूरोसर्जन डॉ. के.डी. खरे एवं नेफ्रोलॉजिस्ट डॉ. मीना पटेल सप्ताह में एक दिन चिकित्सा परामर्श देकर इलाज करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपस्थिति को रायगढ़ मेडिकल कालेज में आने वाले मरीजों के लिए लाभदायक बताया है। उन्होंने कहा कि शासन का प्रयास है कि लोगों को उनके शहरों और गांवों के आसपास ही बेहतर और उच्च चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध हों ताकि उन्हें इलाज के लिए लंबी दूरी न तय करनी पड़े और त्वरित तथा बेहतर इलाज से उन्हें स्वास्थ्य लाभ मिले। अस्पताल अधीक्षक डॉ.

एम. के. मिंज ने बताया कि न्यूरोसर्जन डॉ. नितीश नायक (मस्तिष्क/रीढ़ की हड्डी के सर्जन), प्रत्येक मंगलवार प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक, यूरो सर्जन डॉ. के.डी. खरे (मूत्ररोग विशेषज्ञ)शुक्रवार को चिकित्सालय के भूतल में सर्जरी विभाग की ओ.पी.डी. कक्ष क्रमांक 01 में और नेफ्रोलॉजिस्ट डॉ. मीना पटेल (किडनी / गुर्दा रोग विशेषज्ञ) चिकित्सालय के प्रथम तल में मेडिसिन विभाग के ओ. पी.डी. कक्ष क्रमांक 01 में सप्ताह के प्रत्येक शुक्रवार प्रातः (सुबह) 10:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक चिकित्सा परामर्श के लिए उपलब्ध रहेंगे।

19 से 25 दिसंबर तक कोरिया जिले में मनाया जाएगा 'सुशासन सप्ताह-प्रशासन गांव की ओर

जिला और तहसील मुख्यालयों में लगाए जाएंगे विशेष शिविर लोगों की शिकायतों का किया जाएगा त्वरित समाधान

कोरिया

जनसेवा की गुणवत्ता को और बेहतर बनाने तथा सुशासन की पहुंच हर नागरिक तक सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 19 से 25 दिसंबर 2025 तक जिले में 'सुशासन सप्ताह-प्रशासन गांव की ओर' अभियान विशेष रूप से आयोजित किया जाएगा। इस राष्ट्रीय पहल के लिए भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों व जिलों के कलेक्टरों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। कलेक्टर श्रीमती चन्दन त्रिपाठी ने आज कलेक्ट्रेट स्थित सभाकक्ष में विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक लेकर स्पष्ट निर्देश दिए कि सप्ताह भर चलने वाले इस अभियान में विशेष शिविरों का आयोजन



अनिवार्य रूप से किया जाए तथा नागरिकों की शिकायतों और सेवा-संबंधी समस्याओं का स्थल पर ही त्वरित निराकरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि इस अभियान का मूल उद्देश्य है प्रक्रियाओं को सरल बनाना, सेवाओं को सुगम करना और पारदर्शिता के साथ शासन का लाभ प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाना।

अभियान दो चरणों में संचालित होगा

पहला चरण 11 से 18 दिसंबर 2025 के तहत अभियान से जुड़ी गतिविधियों को सरकार के पोर्टल पर मैप किया जाएगा।सुशासन से संबद्ध प्रमुख लक्ष्यों की पहचान की जाएगी, सार्वजनिक सेवाओं और शिकायत निवारण की प्रार्थमिकताओं का निर्धारण किया जाएगा, विभागवार लक्ष्यों का निर्धारण और आवश्यक तैयारियों की जाएगी।

दूसरा चरण में 19 से 25 दिसंबर 2025 अवधि में प्रतिदिन जिला व तहसील मुख्यालयों पर विशेष शिविर लगाए जाएंगे, जिनमें विभिन्न प्रकार की शिकायतों और जनसेवा आवेदनों का समाधान किया जाएगा। प्रतिदिन पोर्टल पर अपलोड की जाएंगी

महत्वपूर्ण जानकारीयें जैसे शिविरों में निपटाई गई शिकायतों की संख्या, सीपीजीआरएएमएस एवं राज्य पोर्टलों की शिकायतों के समाधान का विवरण, ऑनलाइन सेवा वितरण में जोड़ी गई नई सेवाएँ, निस्तारित आवेदनों की संख्या, सुशासन की उत्कृष्ट पहलें और उनसे जुड़ी तस्वीरें, शिकायतों के समाधान की सफ़लता कहानियाँ, 23 दिसंबर को आयोजित होने वाली जिला स्तरीय प्रसार कार्यशाला का संपूर्ण विवरण।

शासन ने स्पष्ट किया है कि यह अभियान सुशासन की अवधारणा को जमीनी स्तर तक ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। पोर्टल पर अपलोड होने वाले आंकड़े यह बताएंगे कि जिले में अभियान कितना प्रभावी रहा और किस स्तर तक अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुए। कलेक्टर श्रीमती त्रिपाठी ने स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, समाज कल्याण, बिजली, पशुपालन, श्रम, पंचायत एवं आदिमजाति विकास जैसे विभिन्न विभागों को व्यापक तैयारी के निर्देश दिए हैं, ताकि सुशासन सप्ताह को जिले में सार्थक, प्रभावी और जनता के लिए उपयोगी बनाया जा सके।

शिक्षा के घर के लिए शाला शेड निर्माण शाला प्रबंधन समिति मारी ने कराया

मोहला

शाला सच मे बच्चों के शिक्षा का घर -द्वार है और इस घर-द्वार को शाला प्रबंधन समिति और पालक गण अपनी मेहनत और एकजुटता के साथ मिलकर बच्चों की शिक्षा के लिए और उनके भविष्य के लिए समर्पित होकर कार्य करते है तो वास्तव मे शिक्षा जगत को गौरवान्वित होने का एहसास दिलाता है, यही कहावत को पुनः चरितार्थ करते हुए शासकीय प्राथमिक शाला मारी के शाला प्रबंधन समिति और पालकगणो ने अपने बच्चों के हितो को देखते हुए शाला शेड का निर्माण अपनी मेहनत और लगन से बना दिया है, शासकीय प्राथमिक शाला मारी के दर्ज संख्या उन्पत्ती है और नया शाला भवन बनने उसमे कम जगह होने और अनेक मुश्किलों का सामना बच्चों और शिक्षको को करना पड़ा।लाईट, कन्या शौचालय, किचन आदि कि समस्या पुर्वत बनी



हुई है बच्चों को भोजन करने और बैठने की व्यवस्था पूरी नहीं हो रही थी, इस समस्याओ को देखते हुऐ शाला प्रबंधन समिति कि अध्यक्ष श्रीमति अनिता रावत एवं उपाध्यक्ष श्री सुदर्शन कोलियारे और शिक्षाविद श्रीमति नारायणी साहु तथा कार्य का जिम्मेदारी लोचन साहु द्वारा अपने सतत प्रयास से सभी सदस्यों के साथ लकड़ी, बल्ली, सीमेन्ट सीट, बांस,पाइप की आवश्यकता को पुप करते हुए एक

साथ मिलकर शाला शेड का निर्माण किया गया। ज्ञातव्य है कि शाला प्रबंधन समिति मारी द्वारा किचन शेड का भी निर्माण पूर्व मे भी कराया गया था, इस कार्य को शाला प्रबंधन समिति के सदस्य तुकाराम गवर्ना, श्रीमति कौशल्या कोलियारे ,पवन साहु, रोहित साहु, रोहित कुन्जाम, श्रीमति शुभोबाई, श्रीमति सुना बाई, विमला बाई, त्रिभुवन साहु, आदी ने शाला को बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत है।

आज जिले भर में 1529.08 क्विंटल हुई धान खरीदी : समर्थन मूल्य से किसानों में उत्सव जैसा उत्साह



एमसीबी

खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लिए गए ऐतिहासिक निर्णय ने किसानों को वह सम्मान दिलाया है जिसकी प्रतीक्षा वे वर्षों से कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रति एकड़ 21 क्विंटल तक धान खरीदी और 3100 रुपए प्रति क्विंटल के अभूतपूर्व समर्थन मूल्य ने कृषि क्षेत्र में नई ऊर्जा, विश्वास और आर्थिक मजबूती का संचार किया है।

इस पहल से न केवल किसानों को आर्थिक सुरक्षा मिली है, बल्कि ग्रामीण बाजारों में व्यापारिक गतिविधियाँ बढ़ी हैं, जिससे खेती जरूरतों की पूर्ति सहज हुई है और किसान स्वावलंबन की दिशा में मजबूत कदम बढ़ा रहे हैं। भुगतान की प्रक्रिया सीधे किसानों के बैंक खातों में होने से पारदर्शिता, विश्वास और त्वरित आर्थिक सहायता

सुनिश्चित हुई है, जिससे किसान सतोष और भरोसे के साथ खरीदी व्यवस्था का लाभ उठा रहे हैं। आज जिले के 25 उपार्जन केंद्रों में 1529.08 क्विंटल हुई धान खरीदी-एमसीबी जिले के सभी 25 उपार्जन केंद्रों में आज समिति द्वारा एवं टोकन एप्प के माध्यम से धान खरीदी में उल्लेखनीय तेजी दर्ज की गई। समितियों की सक्रियता और सरकार की सुदृढ़ व्यवस्था की वजह से बड़ी संख्या में किसान समर्थन मूल्य पर धान विक्रय के लिए केंद्रों तक पहुंचे। आज जारी आंकड़ों के अनुसार कुल 323 टोकन के माध्यम से 1529.08 क्विंटल धान की खरीदी की गई। जिले के सभी केंद्रों में किसानों की निरंतर भागीदारी उत्साहजनक रही, जिनमें सर्वाधिक प्रभाव केलहारी, कोड़ा, माड़ीसरई, जनकपुर और सिंगरौली उपार्जन केंद्रों में दिखाई दिया। आज की सबसे अधिक

खरीदी केलहारी उपार्जन केंद्र से हुई जहां किसानों द्वारा 23 टोकन के माध्यम से 106.96 क्विंटल धान की आपूर्ति की गई, जो दिन की सबसे बड़ी उपलब्धि रही। इसके बाद कोड़ा उपार्जन केंद्र में 16 टोकन के माध्यम से 95.04 क्विंटल धान की खरीदी दर्ज की गई, जिससे यह स्पष्ट होता है कि किसान समिति और टोकन प्रणाली को सहजता से अपना रहे हैं और व्यवस्थाओं पर पूरा भरोसा कर रहे हैं।

माड़ीसरई उपार्जन केंद्र में आज 19 टोकन के माध्यम से 92.20 क्विंटल खरीदी के साथ तीसरे स्थान पर रहा। वहीं जनकपुर उपार्जन केंद्र पर भी किसानों का उत्साह देखने योग्य था जहां 14 टोकन के माध्यम से 90.58 क्विंटल धान की खरीदी दर्ज की गई, जबकि सिंगरौली उपार्जन केंद्र ने 20 टोकन के साथ 81.10 क्विंटल खरीदी कर अपनी सक्रियता बनाए रखी। इन उपार्जन

केंद्रों पर न केवल किसानों की उपस्थिति अधिक रही बल्कि समिति स्तर पर व्यवस्था, मापन, परिवहन और टोकन प्रबंधन की सफलता भी स्पष्ट रूप से देखने को मिली। फेटो अपलोड सत्यापन के साथ पूरी खरीदी पारदर्शी, डिजिटल और सुरक्षित प्रक्रिया में संपन्न हुई जिससे प्रत्येक किसान को सही और वास्तविक लाभ सुनिश्चित हुआ।

एमसीबी जिला बढ़ रहा मजबूत कृषि अर्थव्यवस्था की ओर- इस वर्ष धान खरीदी में प्रदेश के सबसे सक्रिय और अग्रणी जिलों में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। निरंतर बढ़ती खरीदी, किसानों की बढ़ी भागीदारी और भुगतान की त्वरित व्यवस्था इस बात का प्रमाण है कि आने वाले दिनों में खरीदी और अधिक तेजी से बढ़ेगी तथा जिले की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को और अधिक मजबूती प्राप्त होगी।

मनेंद्रगढ़ में मचा हड़कंप : वनवासी कन्या छात्रावास में घुसी मादा भालू, छात्राएं दहशत में, एक व्यक्ति को किया घायल



एमसीबी/मनेंद्रगढ़

नगर पालिका क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब बुधवार सुबह एक मादा भालू अपने दो शावकों के साथ अचानक वनवासी कन्या छात्रावास परिसर में पहुंच गई। छात्रावास में मौजूद छात्राएं भालू को देखकर भयभीत हो गईं और कमरे के भीतर ही खुद को बंद कर लिया। लगभग पूरे परिसर में अफा-तफरी जैसा माहौल बन गया और छात्राएं

कंपकंपती आवाज़ में लगातार मदद की पुकार करती रहीं।

वार्ड नंबर 17 में व्यक्ति पर हमला, इलाज जारी

इसी दौरान, भालू छात्रावास के पास से निकलकर वार्ड नंबर 17 की ओर बढ़ गई, जहां उसने सुबह करीब उसी समय एक व्यक्ति पर हमला कर उसे बुरी तरह घायल कर दिया।

स्थानीय लोगों ने किसी तरह उस

व्यक्ति को बचाकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहाँ उसका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों के अनुसार घायल व्यक्ति की स्थिति फ़िलहाल स्थिर बताई जा रही है।

वन विभाग और प्रशासन की टीम मौके पर जुटी

घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम, पुलिस बल और स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे। क्षेत्र को घेरते हुए लोगों के आवागमन पर रोक लगा दी गई। वन विभाग की टीम भालू और उसके दोनों शावकों को सुरक्षित जंगल की ओर वापस ले जाने की कोशिश में जुटी है।मौके पर स्थिति का जायजा लेने एसडीएम लिंगराज सिदार, सरजू यादव, तथा नगर पालिका उपाध्यक्ष धर्मेन्द्र पटवा भी पहुंचे। अधिकारियों ने छात्रावास प्रबंधन से बातचीत कर क्षेत्र को सुरक्षित करने का निर्देश दिया और वन विभाग को जल्द से जल्द भालू को पकड़ने या सुरक्षित दिशा में छोड़ने की रणनीति बनाने को कहा।

3 महीनों से भालू के घूमने से दहशत

स्थानीय लोगों के अनुसार यह मादा भालू पिछले लगभग तीन

महीनों से मनेंद्रगढ़ और आसपास के इलाकों में अपने दो शावकों के साथ घूम रही है। कई बार इसे बस्ती और खेतों के आसपास देखा जा चुका है। लोगों का कहना है कि भालू भोजन की तलाश में अक्सर मानव बस्ती क्षेत्रों में प्रवेश कर जाती है, जिससे लगातार भय का माहौल बना हुआ है।

लोगों में डर, प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग

घटना के बाद नगर के लोगों में भारी नाराजगी और भय देखने को मिल रहा है। अभिभावकों ने छात्रावास में अपनी बेटियों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। लोगों की मांग है कि वन विभाग उचित कार्रवाई कर जल्द से जल्द इस मादा भालू को आबादी वाले क्षेत्रों से दूर सुरक्षित स्थान पर छोड़े।

वन विभाग की अपील

वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि भालू को देखने पर भीड़ जमा न करें और उसे उकसाने वाली किसी भी गतिविधि से बचें। टीम ने कहा कि वे पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी प्रकार की जान-माल की हानि न हो और भालू को सुरक्षित तरीके से जंगल में वापस भेजा जा सके।

जिला पंचायत सीईओ का कड़ा निर्देश समय पर जियो टैगिंग और गुणवाापूर्ण निर्माण ही सर्वोच्च प्राथमिकता

जिला पंचायत सीईओ ने विभागीय योजनाओं का किया गहन समीक्षा



एमसीबी

जिले के अमृतधारा स्थित जिला संसाधन केंद्र सभागार में आज जिला पंचायत सीईओ श्रीमती अंकिता सोम ने विभागीय योजनाओं की निदेश समीक्षा बैठक का नेतृत्व किया। जिले में चल रहे सभी निर्माण एवं विकास कार्यों की धरातली प्रगति पर विशेष चर्चा करते हुए उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि निर्माण कार्यों में जियो टैगिंग कार्य पर अपडेट हो, स्थल चयन में भू-सत्यापन का विशेष ध्यान रखा जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि विवादित भूमि पर किसी भी प्रकार का निर्माण न किया जाए।

सीईओ ने कहा कि योजनाओं की सफलता का वास्तविक पैमाना निर्माण की गुणवत्ता और समय सीमा का पालन है। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना एवं प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना के ग्राम पंचायतवार प्रगति प्रतिवेदन की समीक्षा की गई। आर-सेटी के माध्यम से किए गए

राजमिस्त्री प्रशिक्षण कार्यक्रम की प्रगति पर भी चर्चा की गई और तय लक्ष्यों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण आवास समयावधि में पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। जिला पंचायत सीईओ ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि ऐसे सभी हितग्राहियों की पहचान कर कार्यवाही की जाए जिन्होंने आवास राशि प्राप्त कर ली है, लेकिन निर्माण में रुचि नहीं ले रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि आवास राशि का गबन करने वालों पर वसूली की कार्रवाई अनिवार्य रूप से की जाए और किसी भी स्थिति में शिथिलता न बरती जाए।

अमृत सरोवर से आजीविका डबरी तक सभी लंबित कार्य को जल्द पूरा करने के निर्देश-मनरेगा योजना के तहत अमृत सरोवर, आजीविका डबरी, नवीन आंगनवाड़ी भवन निर्माण, महिला मानव दिवस सृजन, मजदूरों को समयबद्ध भुगतान, मांग आधारित रोजगार उत्पन्नता, कृषि आधारित कार्य, जल संरक्षण, प्रॉजेक्ट उवति सहित सभी भौतिक एवं वित्तीय



प्रगति की समीक्षा की गई। सीईओ ने लंबित कार्यों को अविलंब पूर्ण कराए जाने तथा युक्तिधारा पोर्टल पर सभी पंचायतों की कार्ययोजना समय पर अपडेट करने को अनिवार्य किया। उन्होंने कहा कि मनरेगा ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, इसलिए किसी भी स्तर पर देरी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

स्वच्छ मिशन, सामुदायिक शौचालय, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन एवं फ़िक्कल स्लज प्लांट के सुचारु संचालन पर विशेष जोर-स्थिति में शिथिलता न बरती जाए। अमृत सरोवर से आजीविका डबरी तक सभी लंबित कार्य को जल्द पूरा करने के निर्देश-मनरेगा योजना के तहत अमृत सरोवर, आजीविका डबरी, नवीन आंगनवाड़ी भवन निर्माण, महिला मानव दिवस सृजन, मजदूरों को समयबद्ध भुगतान, मांग आधारित रोजगार उत्पन्नता, कृषि आधारित कार्य, जल संरक्षण, प्रॉजेक्ट उवति सहित सभी भौतिक एवं वित्तीय

प्रभाव का मूल्यांकन किया गया। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाई और फ़िक्कल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट के सुचारु संचालन को भी प्राथमिकता में रखने के निर्देश देते हुए सीईओ ने कहा कि स्वच्छता मॉडल तभी सफल माना जाएगा जब उसका धरातली लाभ नागरिकों तक निरंतर रूप से पहुंचता रहे। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, सहायक परियोजना अधिकारी मनरेगा, अनुविभागीय अधिकारी आरईएस, जिला समन्वयक स्वच्छ भारत मिशन, पीएमएवाई पदाधिकारी, खंड स्वच्छता अधिकारी, कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा, तकनीकी सहायक एवं सभी ब्लॉक समन्वयक उपस्थित रहे। समीक्षा के अंत में जिला पंचायत सीईओ ने स्पष्ट संदेश दिया कि जिले की हर विकास योजना का उद्देश्य ग्रामीणों तक लाभ पहुंचाना है और इसे सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक अधिकारी अपनी जवाबदेही के साथ दायित्वों का निर्वहन करें।

मुय मार्ग पर दर्दनाक हादसा टला, तेज़ रतार कार ने खड़ी पिकअप को मारी टक्कर,

दे बच्चों को बचाते हुए हुआ हादसा, बड़ा नुकसान, कोई जर्नहानि नहीं

वरचा कॉलरी/कोरिया

नगर पालिका शिवपुर चरचा के मुख्य मार्ग पर बीती रात लगभग 8 बजे एक तेज़ रफ़्तार कार और खड़ी पिकअप में जोरदार भिड़ंत हो गई। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि आसपास अफ़ा-तफ़री का माहौल बन गया, लेकिन राहत की बात यह रही कि कार में सवार व्यक्ति सहित किसी को भी कोई शारीरिक चोट नहीं आई। सूत्रों के अनुसार बैक़ुंठपुर से सामान लेकर आई पिकअप पिकअप क्रमांक सीजी 16 सीक्यू 8827, नेपाल गेट मुख्य मार्ग स्थित किराना दुकान के सामने खड़ी थी और उस समय माल उतारने का काम चल रहा था। इसी दौरान कार क्रमांक सीजी 29 एडि 8367 सुभाष नगर चौक की ओर से तेज़ रफ़्तार में आते हुए अनियंत्रित होकर पीछे से पिकअप में जा घुसी।प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कार चालक नशे की हालत में था और मुख्य मार्ग पर अचानक सामने आए दो बच्चों को बचाने के प्रयास में, जिसे पिकअप से जा टकराया, वाहन से बड़ा हादसा टल गया।

वाहनों को भारी नुकसान

टकर में पिकअप का पिछला हिस्सा बुरी तरह डैमेज हो गया। कार



के बोनट का एक साइड पूरी तरह चकनाचूर हो गया।घटना के बाद स्थल पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई।

पुलिस ने तुरंत की कार्रवाई

घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी प्रमोद पांडेय ने स्टॉफ को मौके पर भेजा।कार चालक और वाहन को पुलिस द्वारा थाने ले जाया गया। आगे की जांच प्रक्रिया जारी है।

दुकानदारों की सड़क पर कब्जे से बड़ रहा दुर्घटनाओं का खतरा

स्थानीय निवासियों ने नाराजगी जताते हुए कहा दुकानदारों ने दुकानें

सड़क तक बढ़ा ली हैं। सामान उतारने वाले वाहनों को मजबूरन सड़क पर खड़ा करना पड़ता है। इस वजह से मुख्य मार्ग पर आए दिन दुर्घटनाएँ हो रही हैं।लोगों कि वे पूरी कोशिश व प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा ना कोई व्यवस्था, ना कोई निगरानी हादसा होना अब आम बात हो गई है।

निष्कर्ष

कल की घटना में खुशकिस्मती से जनहानि नहीं हुई, लेकिनसड़क अतिक्रमण, नशे में ड्राइविंग और मालवाहक वाहनों की मजबूरन पार्किंग की मिलीजुली स्थिति किसी दिन बड़ी दुर्घटना का रूप ले सकती है।स्थानीय लोगों ने शासन प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की है।

कवर्धा में उत्कृष्ट चिकित्सा सेवाओं के लिए चिकित्सकों का आभार : उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा

उपमुख्यमंत्री ने चिकित्सकों का सम्मान कर साथ किया रात्रि भोज

जिले के सुदूर वनांचलों में स्वास्थ्य शिविर लगाकर लोगों की सेवा करने वाले चिकित्सकों को भी किया सम्मानित

कवर्धा

कवर्धा में स्वास्थ्य सुविधाओं को उत्कृष्ट बनाने के लिए अपना योगदान देने वाले चिकित्सकों के सम्मान में समारोह का आयोजन उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा द्वारा किया गया। इस अवसर पर कवर्धा के जिला अस्पताल एवं निजी अस्पतालों के चिकित्सक उपस्थित रहे। उपमुख्यमंत्री ने सभी के साथ इस समारोह में शामिल हुए और सभी को साल श्रौपल भेंट कर सम्मानित कर सभी के साथ रात्रि भोज किया। उन्होंने सभी से कवर्धा में चिकित्सा सेवाओं को और बेहतर बनाने पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने जिले के सुदूर वनांचलों में स्वास्थ्य शिविर लगाकर लोगों की सेवा करने वाले चिकित्सकों को विशेष रूप से सम्मानित किया। उन्होंने सभी को



चिकित्सकों से कवर्धा में उत्कृष्ट चिकित्सा सेवाओं के लिए चिकित्सकों का आभार व्यक्त किया और कहा कि चिकित्सक आधे भगवान होते हैं किसी भी आपात स्थिति में लोगों की जान बचाने का कार्य करते हैं, यह काम सेवा भावना से ही किया जा सकता है। यहां कवर्धा के स्थानीय चिकित्सकों के साथ बाहर से आये चिकित्सकों ने भी कवर्धा को अपना कर यहां के लोगों को पूरे मन से सेवा की है जिसके लिए पूरा कवर्धा आपका आभारी है। उन्होंने बताया कि कवर्धा स्वास्थ्य सुविधाओं के

विस्तार के लिए 50 बिस्तरीय मातृत्व एवं शिशु अस्पताल हेतु 40 पद की स्वीकृति, जिला अस्पताल कबीरधाम में 16.63 करोड़ की लागत से किटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक, सिटी स्कैन, अत्याधुनिक इंट्रोगेटेड पब्लिक हेल्थ लैब, ओटी एवं हमर लैब में पाँवर बैकअप प्रणाली, जिला चिकित्सालय कबीरधाम की क्षमता 100 बिस्तर बढ़ाकर 220 बिस्तर करने एवं इसके लिए 258 नवीन पदों को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पिपरिया एवं

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रेंगाखार को एम्बुलेंस, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बोड़ला में सोनोग्राफी मशीन प्रदान किया गया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बोड़ला में रहने हेतु शासकीय आवास, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पिपरिया एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सहसपुर लोहारा में पब्लिक हेल्थ यूनिट का शुभारंभ किया गया है। उपस्वास्थ्य केन्द्र राजा नवागँव को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तेरगाँव को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन किया गया। सबसे अहम 318.27 करोड़ रूपए की लागत से मेडिकल कॉलेज निर्माण की स्वीकृति मिली है जिससे अब कवर्धा मेडिकल हब बनने जा रहा है। यहां महानगरों जैसी सुविधाएं प्राप्त हो सकेंगी। उपमुख्यमंत्री ने सभी चिकित्सकों को बताया कि आगामी 11 दिसम्बर को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के द्वारा कवर्धा मेडिकल कॉलेज की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा पूजित आधार शिला का शिलान्यास किया जाएगा। इस ऐतिहासिक अवसर का साक्षी बनने के लिए उन्होंने सभी को आमंत्रित किया।

सोनखान ड्यूटी जा रहे हॉस्टल अधीक्षक की सड़क दुर्घटना में मौत



कसडोल

शासकीय प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास में पदस्थ अधीक्षक मोहर साय अजय की आज सुबह 8:30 बजे अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मौके पर मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार आज सुबह 10 दिसम्बर को शहीद वीर नारायण सिंह के शहादत दिवस के अवसर पर उनकी ड्यूटी सोनखान में लगाया गया था वही ड्यूटी के लिए सुबह कसडोल घर से निकले थे वहीं सोनखान से ठीक



पहले बंगला पाली के समीप अज्ञात वाहन को टक्कर से सिर के गंभीर रूप से चोट लगने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों को सूचना मिलने के बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कसडोल लाया गया। जहां

डॉक्टरों ने मृत घोषित किया गया। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद कसडोल एसडीएम तहसीलदार सहित कसडोल विधायक संदीप साहू भी पहुंचे हैं, इधर स्थानिय स्वास्थ्य केंद्र में पोस्ट मार्टम कराया जा रहा है।

13 दिसंबर को आयोजित होगी नेशनल लोक अदालत, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने की तैयारियां पूरी

कोरिया

जिला मुख्यालय बैकुण्ठपुर में आगामी 13 दिसंबर 2025 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बैकुण्ठपुर द्वारा जारी सूचना के अनुसार विभिन्न प्रकार के लॉबित मामलों के निराकरण हेतु यह राष्ट्रीय लोक अदालत न्यायालय परिसर में आयोजित की जाएगी। इसके लिए सभी तैयारी पूर्ण कर ली गई है। लोक अदालत का उद्देश्य लॉबित मामलों का त्वरित, सस्ता और सौहार्दपूर्ण निपटारा करना है। इसके विशेष रूप से बैंक संबंधी मामले, बिजली बिल विवाद, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, चेक बाउंस, पारिवारिक व अन्य दीवानी मामले



शामिल होंगे। पक्षकारों को आपसी सहमति से मामले निपटाने का अवसर प्रदान किया जाएगा, जिससे समय और धन दोनों की बचत होगी। साथ ही लोक अदालत में निपटार गए मामलों पर अपील का अधिकार सीमित होने से निर्णय अंतिम रूप से प्रभावी हो जाता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि इच्छुक पक्षकार अपने सभी संबंधित दस्तावेजों के साथ निर्धारित तिथि पर उपस्थित होकर इस अवसर का लाभ ले सकते हैं।

प्राधिकरण द्वारा व्यापक जनजागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक लोग लोक अदालत की सुविधा का लाभ ले सकें। फोन नंबर 07836-299019 एवं ईमेल dlsa.koria@gmail.com पर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपने लॉबित मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित हों।

ग्राम बड़े कलकसा की बेटे तेज कुंवर सलामे का छाीसगढ़ पुलिस में चयन, गांव एवं क्षेत्र में खुशी की लहर



मोहला

जिले के ग्राम बड़े कलकसा (कोड़ीकसा) निवासी कुमारी तेज कुंवर सलामे, पिता श्री चिताराम सलामे का चयन छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में हुआ है। उनका चयन जिला मोहलाडूमानपुरडूअंबागढ़ चौकी एवं बालोद से अनारक्षित वर्ग के अंतर्गत हुआ है। चयन की जानकारी मिलते ही गांव एवं आसपास के क्षेत्र में हर्ष का माहौल है। वर्तमान में तेज कुंवर नगर सैनिक (हॉस्टल ड्यूटी) के पद पर प्री-मैट्रिक आदिवासी कक्षा छात्रावास, इरागांव (मानपुर) में

अपनी सेवाएँ दे रही थीं। कठिन परिश्रम और दृढ़ संकल्प के बल पर उन्होंने पुलिस विभाग में स्थान प्राप्त किया। तेज कुंवर ग्राम बड़े कलकसा की प्रथम महिला हैं, जिनका चयन छत्तीसगढ़ पुलिस में हुआ है। इसे लेकर पूरे गांव और समाज में गर्व की अनुभूति की जा रही है। समाज के सभी वरिष्ठजनों ने उन्हें हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। परिजनों और ग्रामीणों ने कहा कि कुमारी तेज कुंवर बेहद मेहनती और लगनशील हैं। उन्होंने लगातार परिश्रम कर यह उपलब्धि हासिल की है, जो क्षेत्र की अन्य युवतियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी।

देवभोग पुलिस की बड़ी कार्यवाही 200 किंटल अवैध धान के साथ ट्रक जप्त

देवभोग

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा धान खरीदी 2024-25 सत्र के दौरान अवैध धान परिवहन व भंडारण पर रोकथाम के लिए सख्त निर्देश जारी किया गया है।देवभोग पुलिस ने लगातार अवैध धान कार्यवाही करते हुए देवभोग पुलिस को मुखबि़र की सूचना प्राप्त हुई थी। कि ओडीसा राज्य से एक ट्रक भारी मात्रा धान लाकर छत्तीसगढ़ में खपाने की योजना बनाई जा रही है। सूचना पर तत्काल थाना देवभोग पुलिस ने उरमाल के पास पहुँची सँदिध ट्रक वाहन क्रमांक किछव 04 स॥ 9374 को रोककर जांच किया गया तो 500 कट्ठा धान ट्रक में भरा था। जब वाहन चालक को वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा गया तो किसी प्रकार का दस्तावेज प्रस्तुत नही कर पाया अवैध धान पाये जाने पर देवभोग पुलिस के द्वारा ट्रक एवं धान



को विधिवत जप्त कर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पीएम सूर्यघर मुत बिजली योजना के जागरूकता के लिए लगाए जा रहें शिविर

ग्राम पंचायत कोरॉमटोला व धान उपार्जन केंद्र छछानपहरी में लोगों को किया गया जागरूक

मोहला

विद्युत विभाग द्वारा पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार के साथ ही लोगों को योजना के लाभ की जानकारी देने ग्राम पंचायतों एवं धान खरीदी केन्द्रों में शिविर लगाए जा रहें हैं। जिसके तहत ग्राम पंचायत कोरॉमटोला एवं धान उपाजर्न केंद्र छछानपहरी, बांधाबाजार जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। ग्राम पंचायत कोरॉमटोला में आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के संबंध में व्यापक जानकारी दी गई। इस दौरान विद्युत विभाग के अधिकारियों ने ग्रामीण उपभोक्ताओं को योजना के लाभ



पात्रता तथा आवेदन की प्रक्रिया के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की। ग्रामीणों को बताया गया कि यह योजना घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली लागत कम करने और ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लागू की गई है। इसी प्रकार धान उपाजर्न केंद्र छछानपहरी, बांधाबाजार में

आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसान, उपभोक्ता और स्थानीय ग्रामीण शामिल हुए। ग्रामीणों को बताया गया कि पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत उपभोक्ताओं को सोलर पैनल स्थापना में सहायता दी जाएगी, जिससे घरेलू बिजली खपत का बड़ा हिस्सा मुफ्त हो सकेगा।

दोना-पत्तल मशीन योजना से ढगी, महिलाओं ने दर्ज कराई,नोटिस से खुला राज

कोरिया बैकुंठपुर

कोरिया बैकुंठपुर जिले में दो स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं ने गंभीर आर्थिक धोखाधड़ी का मामला उजागर किया है. देविका और अनामिका स्वयं सहायता समूह की सदस्य महिलाओं ने दो व्यक्तियों नील कमल और सुनील कुमार पर आरोप लगाया है कि उन्होंने दोना पत्तल मशीन उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाकर 20 महिलाओं के नाम से कुल 6 लाख रुपये का बैंक ऋण स्वीकृत करवाया लेकिन पूरी राशि स्वयं हड़प ली.महिलाओं के आरोप क्या हैं?पीड़ित महिलाओं का कहना है कि आरोपियों ने उन्हें यह विश्वास दिलाया था कि दोना और पत्तल बनाने की मशीनें उपलब्ध कराई जाएंगी और तैयार उत्पाद की मार्केटिंग की जिम्मेदारी भी वही संभालेंगी. इतना ही नहीं उन्होंने यह वादा भी किया था कि बैंक में ऋण की मासिक किस्तें वे स्वयं जमा करेंगे ताकि किसी



भी सदस्य पर आर्थिक दबाव न पड़े.आरोपियों के इन आश्वासनों पर भरोसा करते हुए महिलाओं ने ऋण प्रक्रिया पूरी करवाई लेकिन बाद में न तो मशीनें दी गईं और न ही बैंक की किस्तें जमा की गईं. स्थिति तब और गंभीर हो गई जब बैंकों से महिलाओं को बकाया ऋण की किस्तों के संबंध में नोटिस आने लगे और उन्हें पूरे मामले की वास्तविकता का अंदाजा हुआ.धोखाधड़ी से परेशान महिलाएँ पहले जनदर्शन में पहुंचीं, जहाँ उन्होंने पूरे मामले की लिखित शिकायत अधिकारियों को सौंपी.पुलिस में भी शिकायत दर्ज इसके बाद सभी पीड़ित महिलाएँ सिटी कोतवाली बैकुंठपुर पहुँचीं

और थाना प्रभारी को विस्तृत आवेदन देकर आरोपियों के खिलाफकड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की. शिकायत में महिलाओं ने बताया कि दोनों आरोपी लंबे समय से उन्हें धमित कर रहे थे और बार बार मशीनें जल्द उपलब्ध करने का बहाना बनाते रहे लेकिन महीनों बीत जाने के बाद भी कोई व्यवस्था नहीं की गई जिससे यह स्पष्ट हो गया कि मामला सुनियोजित धोखाधड़ी का है.पुलिस ने महिलाओं से प्राप्त आवेदन को संज्ञान में लेते हुए जांच शुरू कर दी है. प्रारंभिक स्तर पर पुलिस ने पीड़ितों के बयान दर्ज कर लिए हैं और बैंक दस्तावेजों समेत संबंधित सभी तथ्य एकत्रित किए जा रहे हैं.पीड़ित महिलाओं का कहना है कि यह घटना न केवल आर्थिक नुकसान है बल्कि उनकी आजीविका और समूह की विश्वसनीयता पर भी गहरा असर डाल रही है. उन्होंने प्रशासन और पुलिस से भरोसा जताते हुए शोध कार्रवाई की अपील की है ताकि न्याय मिल सके और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके।

डाक जीवन बीमा के तहत 11 लाख का मृत्यु दावा भुगतान किया गया

कोण्डगांव

विकासखंड कोडगांव के ग्राम गिरोला निवासी धनीराम पोयाम ने भारतीय डाक विभाग से वर्ष 2019 में आठ लाख रुपये का डाक जीवन बीमा लिया था जिसमें उन्होंने लगभग 90 हजार रुपये का प्रीमियम जमा किया था और कुछ दिन पूर्व उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई। जिस पर डाक विभाग ने त्वरित कार्यवाही करते हुए नामिनी उनकी पत्नी श्रीमती जगबती पोयाम को बीमा सहित व्याज की राशि 11 लाख रुपये उनके बचत खाते में अंतरित कर प्रदान किया गया। नॉमिनी श्रीमती पोयाम ने डाकघर के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा डाक जीवन बीमा सभी को अवश्य कराना चाहिए। इस मौके पर उपसंभागीय निरीक्षक आरएस मिश्रा, उपडाकपाल एसएल गोटी, शाखा डाकपाल गिरोला विवेदस दिवान, नईम खान, डिकेश मिर्झा,



अनिल दिवान, आईपीपीबी मैनेजर प्रीतम कुमार गुप्ता सहित डाकघर के कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

लोगों के अधिकारों की सुरक्षा के हो सकारात्मक प्रयास



रमेश सर्राफ धमोरा

मानव अधिकार वे मूल अधिकार हैं जो इस धरती पर प्रत्येक व्यक्ति के पास हैं। मानवाधिकार मौलिक अधिकार और स्वतंत्रता है। मानवाधिकारों में जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, गुलामी और यातना से मुक्ति, राय और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, काम और शिक्षा का अधिकार और बहुत कुछ शामिल हैं। बिना किसी भेदभाव के हर कोई इन अधिकारों का हकदार है। भारत का स्वतंत्रता आंदोलन मानवाधिकारों के लिए प्रेरणा का एक बड़ा स्रोत रहा है।

हम 10 दिसंबर को मानवाधिकारों का उत्सव मनाते हैं। उस दिन की स्मृति में जब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1948 में मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया था। यह घोषणा हमारे समाजों के मानवाधिकार ढांचे की रीढ़ है, जहां हममें से प्रत्येक को बिना किसी भेदभाव के शांति और सुरक्षा के साथ रहने और फलने-फूलने का अधिकार है। 1950 में संयुक्त राष्ट्र ने हर वर्ष की 10 दिसम्बर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाना तय किया था। 75 वर्ष पहले पारित हुआ विश्व मानवाधिकार घोषणा पत्र एक मील का पत्थर है। जिसने समृद्धि, प्रतिष्ठा व शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के प्रति मानव की आकांक्षा प्रतिबिंबित की है। आज यही घोषणा पत्र संयुक्त राष्ट्र संघ का एक बुनियादी भाग है। 10 दिसंबर 2025 को दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण वैश्विक प्रतिज्ञाओं में से एक मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा की 77वीं वर्षगांठ है। 2025 में मानवाधिकार दिवस की थीम हमारी रोजमर्रा की अनिवार्यताएं, तीन सरल सत्यों पर जोर देती हैं। मानवाधिकार सकारात्मक हैं, मानवाधिकार आवश्यक हैं, और मानवाधिकार प्राप्य हैं। मानव अधिकार वे मूल अधिकार हैं जो इस धरती पर प्रत्येक व्यक्ति के पास हैं। मानवाधिकार मौलिक अधिकार और स्वतंत्रता हैं। मानवाधिकारों में जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, गुलामी और यातना से मुक्ति, राय और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, काम और शिक्षा का अधिकार और बहुत कुछ शामिल हैं। बिना किसी भेदभाव के हर कोई इन अधिकारों का हकदार है। भारत का स्वतंत्रता आंदोलन मानवाधिकारों के लिए प्रेरणा का एक बड़ा स्रोत रहा है। कुछ अधिकार ऐसे होते हैं जो व्यक्ति को जन्मजात मिलते हैं। उन अधिकारों का व्यक्ति के आयु, प्रजातीय मूल, निवास-स्थान, भाषा, धर्म पर कोई असर नहीं पड़ता। देश के विशाल आकार व विविधता तथा सम्प्रभुता सम्पन्न धर्म-निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणतंत्र के रूप में इसकी प्रतिष्ठा तथा एक भूपूर्व औपनिवेशिक राष्ट्र के रूप में इसके इतिहास के परिणामस्वरूप भारत में मानवाधिकारों की परिस्थिति एक प्रकार से जटिल हो गई है। भारत का संविधान मौलिक अधिकार प्रदान करता है जिसमें धर्म की स्वतंत्रता भी अंतर्भूत है। संविधान की धाराओं में बोलने की आजादी के साथ-साथ कार्यपालिका और न्यायपालिका का विभाजन तथा देश के अन्दर एवं बाहर आने-जाने की आजादी दी गई है। भारतीय परिदृश्य में यह समझ पाना थोड़ा मुश्किल हैकि क्या वाकई में मनुष्य के लिए चिन्हित किये



गए मानवाधिकारों की सार्थकता है।

भारत में 28 सितम्बर 1993 से मानव अधिकार कानून अमल में आया। 12 अक्टूबर 1993 में सरकार ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किया। आयोग के कार्यक्षेत्र में नागरिक और राजनीतिक के साथ आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार भी आते हैं। जैसे बाल मजदूरी, स्वास्थ्य, भोजन, बाल विवाह, महिला अधिकार, हिरासत और मुठभेड़ में होने वाली मौत, अल्पसंख्यकों और अनुसूचित जाति और जनजाति के अधिकार। पूरे विश्व में इस बात को अनुभव किया गया है और इसीलिए मानवीय मूल्यों की अवहेलना होने पर वे सक्रिय हो जाते हैं। इसके लिए हमारे संविधान में भी उल्लेख किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 14,15,16,17,19,20,21,23,24,39,43,45 देश में मानवाधिकारों की रक्षा करने के सुनिश्चित हैं। कहने में मानवाधिकार शब्द बहुत बड़ा है। क्योंकि मानवाधिकारो से हर व्यक्ति का हित जुड़ा होता है। आज के दौर में कोई भी मानव को उनके वास्तविक अधिकार नहीं देना चाहता है। राजनेता मानव अधिकार की बात तो जोशोर से करते हैं।मगर जब अधिकार देने की बारी आती है तो पीछे खिसकने लगते हैं। राज नेताओं को पता है कि यदि लोगों को उनके अधिकार मिल गये तो तो उनकी नेतागिरी बन्द हो जायेगी। हमारे देश के संविधान में मानव को बहुत सारे अधिकार दिये गये हैं। मगर उन पर अमल नहीं हो पाता है। मानव अधिकारों की रक्षा के लिये बनाये गये कानून महज कागजो में सिमट कर रह जाते हैं।

इतिहास गवाह है की भारत ने कभी भी संस्कृति, धर्म या अन्य कारकों के आधार पर दूसरों को अपने अधीन करने की कोशिश नहीं की है। भारत एक ऐसा देश है जिसके मूल में मानवाधिकार की अवधारणा है। भारत के लोग मानवाधिकारों का सम्मान करते हैं और उनकी रक्षा करने का संकल्प भी लेते हैं। भारत विश्व स्तर पर आज भी मानवाधिकार का समर्थन करता रहा है। मानवाधिकार दिवस की नींव विश्व युद्ध की विभीषिका से झुलस रहे लोगों के दर्द को समझ कर और उसको महसूस कर रखी गई थी। किसी भी इंसान की जिन्दगी, आजादी, बराबरी और सम्मान के अधिकार का नाम ही मानवाधिकार है। भारतीय संविधान इन अधिकारों न सिर्फ गारंटी देता है, बल्कि इसे तोड़ने वाले को अदालत सजा भी देती है। पूरी दुनिया में मानवता के खिलाफ हो रहे जुल्मों-सितम को रोकने, उसके खिलाफ संघर्ष को नई परवाज देने में इस दिवस की महत्वपूर्ण भूमिका है। हर शाख को बराबरी का अधिकार देना लोकतंत्र का अहम घटक है। यही वजह है कि आज ज्यादातर सरकार इस अधिकार को कायम करने की कोशिश कर रही है। इसानी अधिकार हमारे अस्तित्व और दुनिया में आत्मसम्मान से रहने की गारंटी होते हैं। हमारी भौतिक और आत्मिक सुरक्षा बरकरार रखते हुए लगातार तरक्की में अहम होते हैं। इसके अंतर्गत भोजन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, शोषण से रक्षा का अधिकार, प्रवास का अधिकार, बाल शोषण, उत्पीडन पर रोक, महिला हिंसा, असमानता, धार्मिक हिंसा पर रोक जैसे कई मजबूत

कानून बनाए गए हैं। यही वजह है कि हर लोकतांत्रिक देश मानवाधिकार अधिकारों की सशक्त पैरवी करते नजर आते हैं। इस दुनिया में जो भी मानव जन्म लेता है उसके साथ उसके कुछ अधिकार भी वजूद में आते हैं। कुछ अधिकार हमें परिवार देता है तो कुछ समाज, कुछ अधिकार हमारा मुल्क देता है, तो कुछ दुनिया। लेकिन आज भी दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो या तो अपने अधिकारों से अंजान है या उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है। कभी जात के नाम पर तो कभी धर्म के नाम पर, कभी लिंग भेदभाव के लिए तो कभी रंग भेद नीति को अपनाकर लोगों के इन अधिकारों को कुचला जा रहा है। हर तबके, हर शहर और दुनिया के कोने-कोने में किसी न किसी वजह से लोगों को बराबरी के हक से महकूम रखने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। इतिहास गवाह है कि दुनिया में हुई बड़ी से बड़ी क्रांति के पीछे अधिकारों का हनन ही अहम वजह रही है। हमेशा ही अपने अधिकारों के लिए इंसान को लंबी जंग लड़नी पड़ी है। दुनिया में तमाम जगह लोगों ने अपन हक की लड़ाई में लाखों कुर्बानियां दी हैं और आज भी बहुत से लोग अपने अधिकारों की जंग लड़ रहे हैं। मानवाधिकारों की रक्षा के लिए कानून बनाये गए और उनको लागू करने या करवाने के लिए प्रयास भी हो रहे हैं। लेकिन वह सिर्फ कागजी दस्तावेज बन कर रह गए हैं। समाज में मानवाधिकारों के होने वाले उल्लंघन के प्रति अगर मानव ही जागरूक नहीं है तो फिर इनका औचित्य क्या है? देखे तो पता चलेगा की कितने मानवाधिकारों का हनन मानव के द्वारा ही किया जा रहा है। मानव के द्वारा मानव के दर्द को पहचानने और महसूस करने के लिए किसी खास दिन की जरूरत नहीं होती है। अगर हमारे मन में मानवता है ही नहीं तो फिर हम साल में पचासों दिन ये मानवाधिकार का झंडा उठा कर घूमते रहे कुछ भी नहीं किया जा सकता है। सरकारी भी मानवाधिकारो का हनन रोक पाने में पूर्णतया सफल नहीं हो पा रही है। देश में आये दिन मानवाधिकार हनन की घटनायें घटित होती रहती है। मगर सरकारी स्तर पर शखा कार्यावाही अमल में नहीं लायी जाती है। जिससे भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृति पर रोक लग सके। यह कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि तमाम प्रादेशिक, राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय सरकारी और गैर सरकारी मानवाधिकार संगठनों के बावजूद मानवाधिकारों का लगातार हनन होता रहता है।

संपादकीय

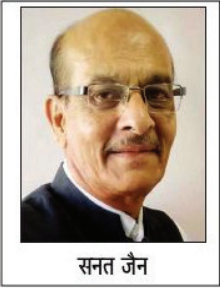
बाबरी बनाम राम मंदिर

तृणमूल कांग्रेस के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने कुछ मुस्लिम चेहरों के साथ बाबरी मस्जिद की नींव रखी, तो दूसरी तरफ बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस, बाबा बागेश्वर और कई साधु-संतों ने, एक व्यापक जन-सैलाब के साथ, 'गीता पाठ' किया। बाबरी मस्जिद से 11 किमी की दूरी पर 'बहरामपुर' में राम मंदिर बनाने का उद्घोष किया गया। इन दोनों फैसलों और कर्मकांडों का धार्मिक आस्था से कोई सरोकार नहीं है। ये सांप्रदायिक, हिंदू बनाम मुसलमान, जमावड़े थे, जिनकी मानसिकता में अप्रैल-मई, 2026 के विधानसभा चुनाव उमड़-धुमड़ रहे थे। बेशक प्रभु श्रीराम समूचे भारत के जनमानस के सबसे अधिक स्वीकार्य और पूजनिय आराध्य हैं। राम के जीवन-चरित पर सबसे अधिक, प्रमुख भाषाओं में, 'रामायण' का सृजन किया गया है। यदि हमारे आराध्य का एक और मंदिर बनाया जाता है, तो वह विवादास्पद नहीं हो सकता, क्योंकि बहुसंख्यक हिंदू 'मूर्ति पूजन' हैं, लेकिन श्रीराम की प्रतीकात्मकता में आराध्य का भव्य मंदिर बन चुका है। मंदिर के शिखर पर सनातन की प्रतीक 'धर्म-ध्वजा' भी सुशोभित की जा चुकी है। देश भर से लाखों श्रद्धालु अपने आराध्य श्रीराम के दर्शन करने और मल्था टेकने अयोध्या जा रहे हैं। राम मंदिर का सम्मान किसी तीर्थ-स्थान से कमतर नहीं है, लिहाजा एक और राम मंदिर के उद्घोष का औचित्य क्या है? देश में आज भी प्रभु राम के असंख्य मंदिर हैं, जहां अनवरत पूजा-पाठ जारी है। बेशक राम के नाम पर ध्रुवीकरण और सामुदायिक लामबंदी जरूरी की जा सकती है। चुनाव के मद्देनजर उनका महत्व भी निर्णायक है। यकीनन हिंदुओं अथवा ऐसे आस्थावानों के ध्रुवीकरण से भाजपा को चुनावी फायदा सर्वाधिक होता रहा है। स्वतंत्र भारत में बाबर जैसे विदेशी आक्रांताओं के स्मारक के तौर पर मस्जिद बनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। भारत अब एक संप्रभु, लोकतांत्रिक और संवैधानिक राष्ट्र है, उसमें बाबर का स्मारक स्वीकार्य नहीं है। मुस्लिम मस्जिद बनाना चाहते हैं, तो सरकार से बाकायदा इजाजत लें और पैगंबर मुहम्मद के नाम पर मस्जिद बनाएं। किसे आपत्ति होगी? हालांकि राजधानी दिल्ली में 'बाबर रोड' आज भी मौजूद है। ऐसे और भी स्मारक बाबर के नाम पर देश में होंगे, लेकिन नए प्रयास, नए शिलान्यास, नए निर्माण को नहीं होने देना चाहिए। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कथित बाबरी मस्जिद की नींव नहीं रखने देनी चाहिए थी। भाजपा के जो चेहरे चीखा-चिल्ली कर बाबरी का विरोध कर रहे थे, उन्हें भी नींव का पुरजोर विरोध करना चाहिए था। मुख्यमंत्री को अपने ही बागी विधायक को गिरफ्तार कराना चाहिए था, लेकिन बाबरी मस्जिद की प्रतीकात्मक नींव रख दी गई और वह तबका अपनी सांपदायिकता में कामयाब रहा। ममता को मुर्शिदाबाद की 24 विधानसभा सीटों पर 65 फीसदी से ज्यादा मुसलमानों के वोट की चिंता थी, तो ममता हिंदुओं के वोट भी छोड़ नहीं सकती थी। बंगाल में 35-40 फीसदी हिंदू वोट ममता की पार्टी के पक्ष में भी जाते हैं, लिहाजा मुख्यमंत्री ने विधायकों को निलंबित ही किया।

चिंतन-मनन

चैतन्य रहें

एक बार दो देवताओं में विवाद हो गया कि भाग्य बड़ा है या पुरुषार्थ? विवाद हर व्यक्ति के मन में पैदा होता है, चाहे मनुष्य हो, चाहे देवता हो। निश्चित हुआ, परीक्षा करें। एक देवता ने कहा- देखो! भाग्य बड़ा नहीं होता, पुरुषार्थ बड़ा होता है। दूसरे ने कहा- नहीं! उस आदमी को देखो। तुम्हें साक्षात् प्रमाणित करूंगा कि पुरुषार्थ बड़ा नहीं होता, भाग्य बड़ा होता है। पति-पत्नी जा रहे थे। देवता ने रास्ते के बीच रत्नों का ढेर लगा दिया। रत्न ही रत्न बिखेर दिए। जब आस-पास आए, पत्नी ने कहा- अभी तो हमारी आंख अन्धली हैं, हम देख सकते हैं, हमें सब कुछ दिखाई देता है। कभी 2सा भी हो सकता है कि बुढ़ापा आने के साथ-साथ हमारी आंखें चली जाएं, हम अन्धे हो जाएं। फिर काम कैसे चलेगा? पति ने कहा - परीक्षा कर लें। देखें, कैसे काम चलेगा? दोनों ने आंखों पर पट्टी बांध ली। दोनों चले। जहां रत्न बिखरे हुए पड़े थे, ढेर लगा था आस-पास में, उससे आगे निकल गए। कुछ आगे जाकर पति बोला- आंखों के बिना काम तो चल जाएगा, 2सी कोई बात नहीं है। खोलो लो पट्टी। पट्टी खोल ली। देवता ने कहा - देखा तुमने। भाग्य में नहीं था, कुछ नहीं मिला। भाग्य बड़ा है पुरुषार्थ से। भाग्य और पुरुषार्थ की चर्चा को हम छोड़ दें किन्तु इस बात को हम नहीं छोड़ेंगे कि जब तक आंख पर मूर्च्छा की पट्टी बंधी हुई है, तब तक हमारे आस-पास में, हमारे सामने, दाएं-बाएं, चारों तरफ जो सम्पदा बिखरी पड़ी है, उसका हमें कुछ भी पता नहीं चलता। हम उस सम्पदा से अनजान रह जाते हैं।



समन जैन

नई पीढ़ी जानेगी वंदे मातरम का इतिहास, मां किसी से भेदभाव नहीं करती... स्वतंत्र भारत की संसद में 75 वर्षों के बाद 'वंदे मातरम' पर हुई चर्चा पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए एक राजनीतिक प्रयास के रूप में शुरू हुई। वंदे मातरम की यह चर्चा एक गीत या नारे तक सीमित नहीं रही। यह बहस पञ्चालन के चुनाव में धार्मिक ध्रुवीकरण, उसकी सांस्कृतिक चेतना और एकता के भाव को समझने का अवसर भी बन गई। संसद में सभी राजनीतिक दलों और सभी सांसदों ने एकजुट होकर वंदे मातरम के पक्ष में बढ़-चढ़कर अपने विचार व्यक्त किये।वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं है। बल्कि वह स्वर है, जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान करोड़ों लोगों के हृदय में देशभक्ति की ज्योति जगाई थी। बलिकचंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित यह गीत आज भी राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक है। इसके



ललित गर्ग

एक बार फिर एक भीषण आग ने 25 मासूम जिंदगियां को छीन लिया। गोवा के नाइट क्लब में हुई यह त्रासदी बलवत्त आगजनी नहीं, बल्कि हमारे सिस्टम की जड़ता, गैर-जिम्मेदारी और नैतिक पतन की ज्वलंत मिसाल है। गोवा का जो नाइट क्लब आग की चपेट में आया, वह नियमों की अनदेखी करके तो चलाया ही जा रहा था, उसमें आग से बचाव के उपाय भी नहीं किए गए थे। रही-सही कसर इससे पूरी हो गई कि नाइट क्लब में आने और जाने का रास्ता बेहद संकरा था। आग की चपेट में आने वालों की संख्या इसलिए अधिक बढ़ गई, क्योंकि बचने के लिए उन्होंने जिस रास्ते को सुरक्षित समझा, वहां पहले से ही लोग फंसे हुए थे। इस तरह से आनंद और उत्सव का स्थल अचानक जीवन समाधि में बदल गया, वह अनेक सवाल हमारे सामने खड़े करता है, क्या हम सीखने की क्षमता खो चुके हैं? क्यों हर हादसे के बाद जांच समितियां बनती हैं, मुआवजा घोषित होता है, कुछ दिन हंगामा होता है और फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाता है? पूर्व में मुंबई, दिल्ली, कोकणाता, सूरत और अनेक शहरों में समान दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। होटल, मॉल, थिएटर, अस्पताल, फ़ैक्ट्री, कोचिंग सेंटर-लापरवाही की आग में झुलसनें वालों की संख्या बढ़ी है, लेकिन हमारी संवेदशीलता का स्तर छोट्टा होता जा रहा है। आगजनी की घटनाओं का सिलसिला तो लगातार है, परंतु सुरक्षा मानकों के प्रति हमारी उदासीनता और घोर लापरवाही भी उतनी ही स्थायी है। यह बात स्पष्ट है कि हादसे किसी तकनीकी गलती का परिणाम भर नहीं, बल्कि प्रशासन और

75 साल बाद संसद में वंदे मातरम की राजनीति?

बोल हर किसी को राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत कर देते हैं।संसद में इस विषय पर हुई चर्चा का सबसे बड़ा महत्व यह है, नई पीढ़ी को वंदे मातरम के ऐतिहासिक महत्व को जानने और समझने का अवसर मिलेगा। युवा पीढ़ी सोशल मीडिया और तकनीक की दुनिया में व्यस्त है। ऐसे विषय पर संसद में जो सार्थक बहस हुई है। वर्तमान पीढ़ी को सोशल मीडिया के माध्यम से बेहतर तरीके से स्वतंत्रता के इतिहास और वर्तमान में प.बंगाल के चुनाव में इस नारे का क्या महत्व है। यह जानने का अवसर मिलेगा। युवा पीढ़ी यह जान सकेगी राष्ट्र की पहचान केवल वर्तमान से नहीं, बल्कि उसके गौरवपूर्ण अतीत से भी बनती है। अंग्रेजों की फूट डालो या किसी भी क्षेत्र से हो। यह गीत किसी एक वर्ग, समुदाय या धर्म का नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र का है। वंदे मातरम को संकीर्ण नजरिये से देखना ना केवल इसके भाव को सीमित करता है। बल्कि राष्ट्रीय एकता अखंडता और भारतीय संस्कृति को भी चोट पहुंचाता है।

हाल के वर्षों में वंदे मातरम को लेकर समय-समय पर राजनीतिक लाभ के बखोस्त होते रहे हैं। कुछ राजनीतिक दल पश्चिम बंगाल की विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए, वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने पर इसे विवाद का विषय बना रहे हैं। संसद में जिस तरह से सभी राजनीतिक दलों ने स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में वंदे मातरम के इस नारे ने स्वतंत्रता की जो लो आम जमानस के बीच में जगाई थी। सबने बढ़ चढ़कर इस नारे के औचित्य को समझाया।संसद में हुई बहस ने यह स्पष्ट किया, देशभक्ति किसी पर थोपी नहीं जा सकती है, अभिव्यक्ति के माध्यम अलग-अलग भी हो सकते हैं। यह दिल से उपजने वाली भावना है। वंदे मातरम का सम्मान करना और उसके भाव को समझना सभी नागरिक अच्छी तरह से जानते हैं। कोई भी अपनी जन्मभूमि को छोड़ना नहीं चाहता है। हां अभिव्यक्ति के तरीके जरूर अलग-अलग हो सकते हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले इसे विवाद का विषय बनाना दुर्भाग्यपूर्ण है। आज जरूरत इस बात की है, हम वंदे मातरम जैसे राष्ट्रीय प्रतीकों को राजनीति से ऊपर उठकर देखें। यह गीत सारे भारत को एक साथ जोड़ता है। इसका एक-एक शब्द सारे भारत का प्रतिनिधित्व करता है। संसद में हुई बहस नई पीढ़ी को स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की भूमिका, संघर्ष और राष्ट्रीय चेतना से जोड़ने में संसद की यह चर्चा सार्थक साबित होगी। वंदे मातरम के नारे का जन्म पश्चिम

गोवा हादसा: झुलसती संवेदनाएं और नाकाम होती व्यवस्था

राजनीतिक मिलीभगत की देन भी हैं। गोवा अपनी पहचान पर्यटन से बनाता है। नाइट लाइफ, समुद्री तटों का आनंद, मनोरंजन गतिविधियां और विदेशी पर्यटक इसका स्वाभाविक आकर्षण हैं। ऐसे प्रेश में इस प्रकार का हादसा केवल मानवीय त्रासदी नहीं, बल्कि छवि और अर्थव्यवस्था का गहरा असर माना भी है। भारत की टूरिज्म इंडस्ट्री पहले ही प्रतिस्पर्धा और सुरक्षा को लेकर चुनौतियां से जूझ रही है। यह घटना विश्व के सामने एक सवाल बनकर खड़ी है-क्या भारत सुरक्षित पर्यटन देश है? क्या यहां गैर-जिम्मेदाराना ढांचे और भ्रष्ट तंत्र के बीच किसी का जीवन सुरक्षित रखा जा सकता है? इस प्रकार के हादसों में दो बड़े चरित्र सामने आते हैं-सरकार की सुरती और अयोगजकों की लालचपूर्ण मानसिकता। अधिकांश नाइट क्लब, बार, पार्क या मनोरंजन स्थल ऐसे होते हैं जहां प्रवेश शुल्क, अवैध संचालन और आर्थिक लाभ का बड़ा खेल चलता है। इमारतों की मंजूरी, फायर सुरक्षा की अनुमति, बिजली के तारों का रखरखाव, निकास मार्ग-ये सभी चीजें फाइलों में तो दर्ज होती हैं, लेकिन जमीन पर गायब रहती हैं। प्रशासनिक अधिकारियों की सजगता की जगह 'संबंध' और 'सुविधा शुल्क' काम करता है। निरीक्षण के नाम पर औपचारिकता ढहती है और बीते हुए हादसे केवल याद बनकर रह जाते हैं। नाइट क्लब तक पहुंचने का रास्ता इतना संकरा है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को 400 मीटर दूर खड़ा होना पड़ा। सजावट के लिए ताड़ के सूखे पत्तों का इस्तेमाल किया गया था, जिसने आग और भड़का दी। भीड़भाड़ वाली जगहों पर एंट्री से ज्यादा महत्वपूर्ण इमरजेंसी एग्जिट पॉइंट्स होते हैं, लेकिन इस क्लब में लगता है कि इसकी भी कोई व्यवस्था नहीं थी, जिससे कई लोग भटक कर किचन में पहुंच गए, जहां से बाहर निकलने का रास्ता नहीं था। यह नाइटक्लब बिना मंजूरी के चल रहा था। लोकल अग्रांटी के मुताबिक, निर्माण अवैध था।

सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि आखिर हम हादसों को नियति क्यों मान लेते हैं? हर घटना के बाद नेताओं के बयान आते हैं-"दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा", "उच्च स्तरीय जांच की जाएगी", "मुआवजा दिया जाएगा",

लेकिन क्या कभी हमने दोषियों को सजा होते देखा है? कभी किसी अधिकारी को बखोस्त होते देखा है? क्या किसी क्लब या होटल की अनुमति स्थायी रूप से रद्द की गई? जवाब अधिकतर 'नहीं' है। यही वह सत्य है जो बताता है कि हमारा समाज हादसे को दुख तो मानता है पर समस्या नहीं मानता। अजीब विडंबना यह है कि हादसे के शिकार गरीब या आम नागरिक होते हैं, लेकिन इस त्रासदी से गुजरी व्यवस्थाओं को कोई चोट नहीं लगती। वे फिर उठते हैं, नए सजावटी बोर्ड लगा लेते हैं और जनता को फिर से आकर्षित कर लेते हैं। व्यवस्था में भ्रष्टाचार और मानव-मूल्यों का हास दोनों मिलकर ऐसी घटनाओं को जन्म देते हैं। यह केवल प्रशासनिक नाकामी नहीं, बल्कि सामूहिक नैतिक ह्रास भी है। आयोगक केवल लाभ देखते हैं; प्रशासन केवल कागजों पर निशान देखता है; समाज घटना को क्षणिक दुख समझकर भूल जाता है। वैश्विक स्तर पर देखें तो किसी भी विकसित या उत्तरदायी समाज में जन-स्थलों पर सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होती है। नियमित निरीक्षण, कठोर दंड, मानकों का अनिवार्य पालन और पारदर्शिता पुनर्जादी तत्व हैं। भारत में ये मानक केवल कानूनी बुनतकों में रहते हैं। सवाल यह नहीं कि हादसे क्यों होते हैं, सवाल यह है कि सीख क्यों नहीं ली जाती। गोवा का यह हादसा एक चेतावनी है, अकेले गोवा के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए। हम विकास, पर्यटन और आधुनिक जीवनशैली की बात करते हैं, लेकिन सुरक्षा, निबंधन और मानवीय संवेदनशीलता को हाशिए पर छोड़ देते हैं। यह घटना बताती है कि यदि व्यवस्था की लापरवाही और लालच के बीच नागरिक की सुरक्षा कुचलती रही तो हम आधुनिक ढांचे बनाकर भी असुरक्षित रहेंगे। किसी भी राष्ट्र की उन्नति उसके नागरिकों की सुरक्षा पर टिकी होती है, न कि केवल चमक-रमक पर।

गोवा घटना ने सरकार की छवि को ध्वस्त किया है। पर्यटन उद्योग की नींव हिलाई है और नागरिक विश्वास को चोट पहुंचाई है। गोवा के जीडीपी में पर्यटन का हिस्सा 16 प्रतिशत से ज्यादा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, पिछले साल की तुलना में इस साल जनवरी

से सितंबर के बीच 6.23 प्रतिशत ज्यादा टूरिस्ट गोवा पहुंचे। ऐसे में यह घटना राज्य की अच्छी छवि पेश नहीं करती, जहां पहले ही टेक्सी चालकों की मनमानी और पर्यटकों के साथ अभद्रता की कुछ समस्या रही है।यदि घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकनी है तो कुछ कठोर कदम उठाने होंगे, जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई, वास्तविक निरीक्षण प्रणाली, भ्रष्टाचार पर अंकुश और सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर दंड। परंतु दुख यह है कि हमारा इतिहास बताता है, हम कठोर कदम उठाने से बचते हैं। आज इस त्रासदी के बाद शोक जताना पर्याप्त नहीं है। इस पर गंभीर चिंतन जरूरी है। हम केवल जिम्मेदारी टाल देने की प्रवृत्ति में नहीं जा सकते। हर हादसा हमें यही याद दिलाता है कि सुरक्षा संस्कृति, जिम्मेदार शासन और नैतिक व्यवसायिक आचरण के बिना कोई भी समाज सुरक्षित नहीं हो सकता। यह घटना केवल 25 लोगों की मौत नहीं, बल्कि चेतावनी है कि हमारा इतिहास बताता है, हम कठोर कदम उठाने से बचते हैं। आज इस त्रासदी के बाद शोक जताना पर्याप्त नहीं है। इस तरह की घटनाएं यही रेखांकित करती हैं कि नया और विकसित बनने के आकांक्षी भारत में नियम-कानूनों की हर स्तर पर उपेक्षा होती है और इस देश में जिम्मेदारी के साथ कोई काम मुश्किल से ही किया जाता है। मानकों और सुरक्षा उपायों की रेगुलर चेकिंग अथॉरिटीज की जिम्मेदारी है। बिना लाइसेंस चल रहे क्लब, होटल या रेस्तरां को बंद कराने के साथ यह जानना भी जरूरी है कि आखिर ये खुल कैसे जाते हैं और फिर कैसे धड़ल्ले से चलते रहते हैं। हमें यह मानना होगा कि जीवन की कोमल केवल शब्दों में नहीं, व्यवस्था की भी झलकनी चाहिए। जब तक हमारी नीतियों में कठोरता नहीं आएगी, जब तक भ्रष्टाचार की जड़ें नहीं काटी जाएंगी और जब तक नागरिक-केन्द्रित शासन स्थापित नहीं होगा, तब तक मनोरंजन के नाम पर मौतें होती रहेंगी। गोवा का नाइट क्लब हादसा केवल आग नहीं-हमारे विवेक, शासन और मानवता की विफलता है। अब यह हमारे हाथ में है कि हम इसे भूलें या इसे परिवर्तन की शुरुआत बनाएं।



कितना सही है नाश्ते में दही लेना

नाश्ते में हम सभी कुछ ऐसा खाना पसंद करते हैं, जो खाने में टेस्टी हो और हमारे शरीर को पूरा दिन काम करने की एनर्जी देता रहे। ऐसे में ज्यादातर लोग किसी ना किसी रूप में नाश्ते में दही खाना पसंद करते हैं। लेकिन क्या नाश्ते में दही लेना एक स्वस्थ विकल्प है?

पाचक होती है लेकिन नींद दिलाती है

- यदि आपके दिन शुरुआत ही दही के साथ हो रही है तो यह आपको एनर्जी देने के स्थान पर नींद दिला सकती है और शरीर में सुस्ती बढ़ा सकती है। इसलिए दही कभी भी आपके फर्स्ट फूड का भाग नहीं होना चाहिए। हालांकि दही नाश्ते का एक शानदार हिस्सा है। यदि आप इसे खाते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखते हैं तब,

समझे विरोधी बातों का अर्थ

- एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि दही नाश्ते में खाना अच्छा है। वहीं दूसरी तरफ यह भी कह रहे हैं कि इसे खाने से सुस्ती बढ़ सकती है। दरअसल, ये दोनों ही बातें सही हैं। दही खाने पर आपको एनर्जी मिलेगी या सुस्ती आएगी, यह इस बात पर निर्भर करता है कि दही खाने का आपका तरीका क्या है।

इस तरह खाएं और इस तरह ना खाएं दही

- आप नाश्ते में चपाती, पराठा, चिल्ला आदि के साथ दही खा सकते हैं। एक कटोरी दही का सेवन नाश्ते में करना शरीर के लाभकारी होता है और पाचनतंत्र को सही करता है। साथ ही शरीर को दिनभर के लिए ऊर्जा देने में लाभकारी होता है।
- लेकिन नाश्ते में दही का सेवन तभी करना चाहिए जब आप सुबह के समय नाश्ते से पहले कुछ खा या पी चुके हों। जैसे, सुबह की शुरुआत आपने पानी के साथ को हो और फिर चाय-टोस्ट, स्क्राउट्स या ड्राईफ्रूट्स आदि खाएं हों। इसके एक घंटे बाद यदि आप नाश्ते में दही का सेवन करते हैं तो आपको नींद नहीं आएगी। आपको गैस बनने की समस्या है तो इन 5 सखियों से बचना चाहिए

खाली पेट नहीं खानी चाहिए दही

- सुबह के समय आप नाश्ते में केवल मीठी दही का उपयोग कर सकते हैं। खट्टी दही खाने से परहेज करें। साथ ही नाश्ते में दही खाते समय आप इसमें एक चम्मच शक्कर मिला सकते हैं। यदि आपको शुगर की समस्या नहीं है तब।
- दिन की शुरुआत यदि किसी भी कारण देरी से हुई हो और आपके पास नाश्ता करने का समय ना हो तो भूलकर भी खाली दही ना खाएं। यदि आप खाली पेट दही खाते हैं तो आपको जबदस्त नींद आएगी और आप खुद को बहुत थका हुआ अनुभव करेंगे।
- ऐसा इसलिए होता है क्योंकि खाली पेट दही खाने से कुछ लोगों को ब्लड प्रेशर कम होने की समस्या हो जाती है। इससे शरीर में ब्लड का फ्लो कम होता है और ऑक्सीजन का स्तर घटने लगता है। यही कारण है कि बहुत तेज नींद आती है और बेहोशी जैसा अनुभव होता है।



आप चाहे मानसिक काम अधिक करते हैं या शारीरिक काम। यदि आपको काम करते समय बहुत जल्दी थकान होने लगती है तो इसका एक अर्थ यह होता है कि आपके शरीर में डिहाइड्रेशन की समस्या है। जी हाँ, केवल पोषण की कमी के कारण ही नहीं बल्कि शरीर में पानी की कमी के कारण भी जल्दी थकान होती है। जो लोग नियमित रूप से जरूरी पानी नहीं पीते हैं, उन्हें काम करते समय अधिक थकान होना और अन्य लोगों की तुलना में जल्दी थकान होने जैसी समस्याएं होती हैं। जानें, जल्दी थकान होने के अन्य कारण और उनके निवारण के तरीके

जल्दी थकने की वजह

- आमतौर पर जो लोग बहुत जल्दी थकान होने की समस्या से पीड़ित होते हैं, उनके शरीर में कुछ खास तत्वों की कमी देखने को मिलती है,
- पानी की कमी
- खून की कमी
- विटमिन-बी12 की कमी
- फोलेट या फॉलिक एसिड की कमी देखने को मिलती है।

जल्दी थकान से बचने के तरीकों में ना केवल अपने खान-पान पर ध्यान देना है बल्कि यह भी ध्यान देना है कि जिस ड्रायट का सेवन आप कर रहे हैं और जिन ड्रिक्स को आप ले रहे हैं, क्या वे आपके शरीर की जरूरतों को पूरा कर रही हैं। यहां जानें कैसे रखा जाएगा इस बात का ध्यान,

तरल पदार्थों का सेवन

- जल्दी-जल्दी होने वाली थकान की समस्या से बचने के लिए जरूरी है कि आप तरल पदार्थों का सेवन बढ़ा दें। इनमें जूस, सूप, छाछ, दाल इत्यादि शामिल हैं। इसके साथ ही समय-समय सादा पानी पीते रहें। वयस्कों को हर दिन कम से कम 8 गिलास पानी पीना चाहिए।

तनाव को नियंत्रित करना सीखें

- जल्दी थकने की एक बड़ी वजह लगातार बना रहनेवाला तनाव भी होता है। तनाव का कारण चाहे जो भी लेकिन यह व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से जल्द थका देता है। इसलिए तनाव से



बचने के लिए हर दिन कुछ समय के लिए मेडिटेशन या नींद ध्यान जरूर करें। यह आपको मानसिक रूप से फिट रखने का काम करेगा।

फलियों का सेवन करें

- हरी फलियां कई तरह की वरायटी में आती हैं। खास बात यह है कि मौसम की प्रकृति और उस दौरान शरीर की जरूरत के अनुसार हर सीजन में आनेवाली फलियां पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं।



चैन की नींद सोना है तो जरूर करें यह काम

अगर आप चाहते हैं कि रात में आपको सुकून की नींद आए, पैरों में कुलन और बेपैनी के कारण आपकी नींद में किसी तरह की बाधा ना आए तो आपको सोने से पहले एक खास काम करना होगा। यह काम आपके शरीर को राहत देने के साथ ही दिमाग को भी शांति देगा। आइए, जानते हैं कि आखिर क्या और कैसे करना है।

आपको क्या करना है ?

- बिस्तर पर जाने से पहले आपको अपने पैर साफ पानी से धुलकर कॉटन के कपड़े से पोछकर साफ करने हैं। इसके बाद सरसों के तेल से अपने पैरों की मालिश करें। यह मालिश 2 से 3 मिनट की भी हो तो काफी है। यहां जानें इस तरह हर दिन मालिश करने से आपको किस तरह के लाभ होंगे,

पैर के तलुए में होते हैं

सभी एक्जुप्रेशर पॉइंट्स

- हमारे पैर के तलुओं में पूरे शरीर के एक्जुप्रेशर पॉइंट्स होते हैं। पैर के तलुओं पर मसाज करने से इन पॉइंट्स पर दबाव पड़ता है, जिससे शरीर का तनाव कम होता है और मानसिक शांति बढ़ती है। इसलिए आप अच्छी नींद आती है।

ताउम्र रहेंगे युवा

- अगर आप हर दिन सोने से पहले अपने पैर के तलुओं पर सरसों के तेल से मालिश करेंगे तो आप ताउम्र युवा बने रहेंगे। यहां युवा बने रहने से हमारा आशय है कि आपके दांत, आपकी दृष्टि और आपके शरीर के जोड़ों में किसी तरह का दर्द या समस्या नहीं हो पाएगी।

चश्मा नहीं लगेगा

- यदि आप सोने से पहले हर दिन अपने पैरों पर सरसों तेल से मालिश करते हैं तो आप अपनी कमजोर आइसाइट को भी ठीक कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको एक या दो हफ्ते में ही इसका असर देखने को मिल जाएगा।

पाचन को ठीक रखे

- आपको जानकर थोड़ी हैरानी हो सकती है। लेकिन यह सही है कि जो लोग नियमित रूप से अपने पैर के तलुओं पर मालिश करते हैं या किसी और से कराते हैं, उनका पाचनतंत्र अन्य लोगों की तुलना में काफी ठीक रहता है। साथ ही उन्हें पेट संबंधी रोग नहीं घेरते हैं।
- साथ ही ऐसे लोगों के शरीर पर थकान हावी नहीं हो पाती है। पैर के तलुओं की मसाज करने से शरीर के डैमेज सेल यानी क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की जल्द मरम्मत होती है। इससे त्वचा भी चमकदार बनी रहती है। तो देर किस बात की, खुबसूरती और सेहत के लिए आज से ही शुरू करें पैर के तलुओं की मालिश।

लगातार बनी रहती है थकान तो ऐसे रखें अपना ध्यान

- हरी फलियां फाइबर युक्त होती हैं और इनका पाचन धीमी गति से होता है। इसलिए ये शरीर को लंबे समय तक ऊर्जा देने का काम करती हैं, जिससे शरीर पर थकान कम हावी होती है।

ड्राईफ्रूट्स

- ऐसा नहीं है कि ड्राईफ्रूट्स का सेवन केवल सर्दियों में ही करना चाहिए। बल्कि सीमित मात्रा में और दूध के साथ ड्राईफ्रूट्स का सेवन गर्मियों में भी हर दिन किया जा सकता है।
- क्योंकि ड्राईफ्रूट्स केवल हमारे शरीर को गर्माहट देने का ही काम नहीं करते हैं बल्कि पोषण देने का काम भी करते हैं। शरीर की कमजोरी को दूर करने में मीट भी अच्छी भूमिका निभाता है। लेकिन कोरोना संक्रमण के दौर में हम आपको मीट खाने की सलाह नहीं देना चाहते हैं। इस समय में आप थकान से बचने के लिए ड्राईफ्रूट्स यानी सूखे मेवों का सेवन कर सकते हैं।



शरीर में ऑक्सीजन की कमी के लक्षण और कारण

शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाना कई रोगों का कारण बनता है। ऑक्सीजन का स्तर कम होने पर सबसे जल्दी और सबसे बुरा असर हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता पर पड़ता है। इस स्थिति में कोई भी वायरस और बैक्टीरिया हमारे शरीर पर हावी हो सकता है। शरीर में ऑक्सीजन की कमी के लक्षण और कारण क्या होते हैं,

शरीर में ऑक्सीजन की कमी के लक्षण

- शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने से अर्थ है कि शरीर को अपनी नियमित क्रियाओं को सुचारु रूप से चलाने के लिए जितनी मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए, उतनी मात्रा में ऑक्सीजन ना मिल पाता।
- जब शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है तो सबसे पहले व्यक्ति को थकान महसूस होती है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती या सांस फूलने लगता है। इसके बाद शरीर में रक्त के प्रवाह की गति धीमी हो जाती है। इससे थकान और घबराहट बढ़ जाती है।

हो सकती हैं ये बीमारियां

- यदि शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो जाए तो ब्रेन डैमेज और हार्ट अटैक तक की स्थिति बन जाती है। शुगर के रोगियों में यदि ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो उनकी शुगर अचानक बहुत अधिक बढ़ सकती है, जो कि एक जानलेवा स्थिति भी बन सकती है।
- ऑक्सीजन का स्तर अचानक से बहुत अधिक घट जाने पर शरीर में थायरॉइड हॉर्मोन का संतुलन गड़बड़ा जाता है। इस स्थिति में थायरॉइड का स्तर या तो बहुत अधिक बढ़ सकता है या बहुत अधिक घट सकता है।

शरीर में ऑक्सीजन की कमी के कारण

- शरीर में ऑक्सीजन की कमी के कई कारण होते हैं, जो व्यक्ति की लाइफस्टाइल पर निर्भर करते हैं। जो लोग बहुत अधिक आलस से भरपूर जीवनशैली जीते हैं यानी फिजिकल ऐक्टिविटी नहीं करते हैं, उनके शरीर में भी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है।
- जो लोग बहुत अधिक शारीरिक श्रम करते हैं लेकिन उसके हिसाब से ड्रायट नहीं लेते हैं, उनके शरीर में भी ऑक्सीजन की कमी हो सकती है।
- जिन लोगों के भोजन में आयरन की मात्रा कम होती है अगर वे लंबे समय तक इसी तरह का भोजन लेते रहें तो उनके शरीर में भी ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। क्योंकि फेफड़ों सहित पूरे शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह करने में आयरन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।



आंखें खे शरीर का सबसे जरूरी, सुंदर और नाजुक अंग हैं। सर्दी के मौसम में नमी और ठंडक के कारण आंखों में पानी आ जाता है लेकिन यह ड्राई आई सिंड्रोम का संकेत भी हो सकता है। इस बीमारी में आंखों से बहुत ज्यादा पानी आना, धुंधला दिखाई देना और चुभन महसूस होना, सूजन, रैशेज, लालपन जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। इस बीमारी का समय पर इलाज न करने पर आंखों की रोशनी जा भी सकती है। ऐसे में इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए आप डॉक्टर की दवाइ के साथ-साथ कुछ घरेलू उपाय भी कर सकते हैं। इन घरेलू नुस्खों की मदद से आप बिना किसी नुकसान के इस परेशानी से छुटकारा पा सकते हैं।

गीला कपड़ा - आंखों को हाथों से इफेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। आंखों में जलन, दर्द या खुजली होने पर साफ पानी में कपड़े को भिगोकर आंखों की सफाई करें। इससे किसी भी तरह की बीमारी का खतरा कम हो जाता है।

नारियल का तेल - नारियल तेल में मौजूद गुण आंखों की गंदगी को साफ करते हैं। रोजाना आंखों के नीचे और आस-पास नारियल के तेल की मालिश करें। आपको इस समस्या से निजात मिल जाएगा।

हर्बल टी - कोमोमाइल या पेपरमिट चाय की पतियों को थोड़ी देर गर्म पानी में भिगो दें। इसके बाद थोड़ी-थोड़ी देर में आंखों की सिकाई करें। ध्यान रहे कि पानी ज्यादा गर्म न हो।

नमक - कई बार आंखों में जलन और खुजली के कारण पानी आने लगता है। ऐसे में आप 1 गिलास गर्म पानी में

चुटकीभर नमक डालकर आंखों की सिकाई करें। दिन में 3 बार इसका इस्तेमाल खुजली और जलन की परेशानी को दूर कर देगा।

बेकिंग सोडा - साफ पानी में 1 चम्मच बेकिंग सोडा मिलाकर गर्म करें। पानी थोड़ा रह जाने पर इससे अपनी आंखों को धो लें। इससे आपको आराम मिल जाएगा। **ठंडा दूध** - कॉटन बॉल को ठंडे दूध में डिप करके अपनी आंखों को आस-पास रगड़ें। इसके अलावा आप कॉटन बॉल को ठंडे दूध में भिगोकर रख भी सकते हैं। इन उपायों को सुबह-शाम करने से आपको आराम मिल जाएगा।

एलोवेरा - एलोवेरा जेल में 1 चम्मच शहद और 1/2 कप एल्डरबेरी चाय मिलाएं। रोजाना दिन में 2 बार इस मिश्रण से अपनी आंखों को धोएं। आपको परेशानी कुछ समय में ही दूर हो जाएगी।

कच्चा आलू - एस्ट्रिजेंट के गुणों से भरपूर कच्चा आलू आंखों में पानी आने की समस्या से जल्दी राहत देता है। आलू की पतली स्लाइस काट कर कुछ देर फ्रिज में रखें। इसके बाद इस टेंडी स्लाइस को 15 से 20 मिनट के लिए आंखों के उपर रख लें। 2-3 दिन तक इसका इस्तेमाल आपकी इस समस्या को दूर कर देगा।

छत्तीसगढ़ में जाति प्रमाण पत्र जारी करने में आ रही बाधाओं को लेकर उपेंद्र जगत ने गृह मंत्री अमित शाह से हस्तक्षेप की माँग की



रायपुर

सामाजिक कार्यकर्ता एवं अधिवक्ता उपेंद्र जगत ने छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति वर्ग के छात्रों को जाति प्रमाण पत्र जारी करने में हो रही गंभीर प्रशासनिक जटिलताओं पर चिंता व्यक्त करते हुए देश के गृह मंत्री अमित शाह से त्वरित हस्तक्षेप की माँग की है। उन्होंने कहा कि घासी-घसिया, गाड़ा, महार, मोची सहित कई अनुसूचित जाति समुदायों के हजारों विद्यार्थी जाति प्रमाण पत्र के अभाव में अपने संवैधानिक अधिकारों से वंचित होते जा रहे हैं। उपेंद्र जगत ने बताया कि प्रदेश के कई जिलों में अधिकारियों द्वारा जाति प्रमाण पत्र के लिए 1950 के पूर्व के दस्तावेज़ अनिवार्य बताए जा रहे हैं, जो व्यावहारिक रूप से उपलब्ध होना लगभग असंभव है। उन्होंने इसे पूर्णतः अव्यावहारिक, असंवैधानिक और सामाजिक न्याय के विरुद्ध बताया। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा 2018 में डॉ. रमन सिंह सरकार और बाद में भूपेश बघेल सरकार द्वारा जाति प्रमाण पत्र प्रक्रिया को सरल करने के



निर्देश जारी किए गए थे, जिनके आधार पर नगर निगम और पंचायत स्तर पर प्रमाण पत्र भी बनाए गए। इसके बावजूद अधिकारियों की कथित लापरवाही और हठधर्मिता के कारण आदेशों का पालन नहीं हो रहा है। ज्ञानकारी के अनुसार, केवल नगर पालिक निगम में ही लगभग 6000 आवेदन लंबित पड़े हुए हैं। उपेंद्र जगत ने उत्तराखंड राज्य का उदाहरण देते हुए कहा कि वहाँ जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए कट-ऑफ़ डेट 1950 के बजाय राज्य

शाह से आग्रह किया है कि— जाति प्रमाण पत्र के लिए 1950 पूर्व की दस्तावेज़ी अनिवार्यता को तुरंत समाप्त किया जाए। राज्य शासन द्वारा जारी सरलीकरण आदेशों का कड़ाई से पालन कराया जाए। संबंधित अधिकारियों पर कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। अनुसूचित जाति वर्ग के छात्र-छात्राओं को बिना बाधा उनका अधिकार मिले। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से लाखों स्त्र/स्त्र युवाओं के भविष्य को नई दिशा मिलेगी और सामाजिक न्याय की भावना सुदृढ़ होगी।

— उपेंद्र जगत
अधिवक्ता एवं सामाजिक कार्यकर्ता



अच्छी पहल बताया। इस दौरान राजेश कल्याण सिनीवाली गोयल सहित तिवारी, उप संचालक समाज अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

कवर्धा शहर कांग्रेस कमेटी की मासिक बैठक एवं एसआईआर समीक्षा बैठक आयोजित

शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अशोक साहू ने ली बैठक



कवर्धा

शहर कांग्रेस कमेटी की महत्वपूर्ण मासिक बैठक शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अशोक सिंह ठाकुर की उपस्थिति में मंगलवार को आयोजित की गई। बैठक में बीएलओ, मंडल अध्यक्ष, सेक्टर अध्यक्ष, शहर कांग्रेस पदाधिकारी एवं सक्रिय कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सहभागिता दर्ज कर संगठनात्मक गतिविधियों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक के दौरान कवर्धा शहर के विभिन्न वार्डों के बूथ स्तर पर चल रहे एसआईआर कार्यों की जानकारी ली गई। प्रत्येक बूथ में चल रही

गतिविधियों, मतदाता सूची से संबंधित बिंदुओं एवं संगठन के कार्यों को और अधिक सशक्त बनाने के लिए आवश्यक सुझावों पर विस्तार से चर्चा हुई। पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने अपने-अपने क्षेत्र की रिपोर्ट साझा की और आगामी कार्ययोजना पर महत्वपूर्ण सुझाव भी प्रस्तुत किए। संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने, जनता से निरंतर संपर्क बनाए रखने तथा आने वाले कार्यक्रमों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सामूहिक निर्णय लिए गए। बैठक उत्साहपूर्ण वातावरण में सम्पन्न हुई और सभी कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर कांग्रेस विचारधारा को मजबूती प्रदान करने का संकल्प

लिया जहाँ प्रमुख रूप से उपस्थित रहे शहर अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी कवर्धा अशोक सिंह ठाकुर, संगठन प्रभारी गोपाल चंद्रवंशी, पूर्व अध्यक्ष प्रत्याशी संतोष यादव, एनएसयुआई जिला अध्यक्ष शितेश चंद्रवंशी मंडल अध्यक्ष दीपक ठाकुर, मंडल अध्यक्ष गणेश योगी, खेगेंद्र सेन शहर महामंत्री कवर्धा, जितेंद्र जैन कोषाध्यक्ष शहर कांग्रेस, धीरज सिंह, गुड्डू ठाकुर, देवराज पाली, मेहुल सत्यवंशी, जगदीश गुप्ता, जाहिर कुरेशी, डॉ खिराम साहू, जितेंद्र कौशिक, विसर्जन यादव, अश्वनी कौशिक, रामायण सिन्हा, अफजल खान, मिलन तिवारी, सुरेश वर्मा, नरेन्द्र वर्मा उपस्थित थे।

साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक में विकास कार्यों की प्रगति पर सत निर्देश



बीजापुर

कलेक्टर संजित मिश्रा ने जिले में संचालित सभी विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा करते हुए साप्ताहिक समय-सीमा बैठक में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए। उन्होंने विभिन्न विभागों में चल रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा कर गति लाने पर जोर दिया। बैठक में कलेक्टर ने विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यों की समीक्षा की और प्रगति की विस्तृत जानकारी ली। इसके साथ ही बस्तर ओलंपिक के संभागीय स्तर के आयोजन को ध्यान में रखते हुए चर्यनित खिलाड़ियों के आवागमन, ठहरने और भोजन व्यवस्था को पूर्णतः सुरक्षित और व्यवस्थित रखने के निर्देश दिए। उन्होंने संभागीय नोडल अधिकारियों से सतत

समन्वय बनाकर कार्य करने पर बल दिया। कलेक्टर ने बताया कि 14 दिसंबर को प्रस्तावित विधानसभा सत्र को ध्यान में रखते हुए सभी विभाग समय-सीमा में विधानसभा प्रश्नों के उत्तर उपलब्ध कराएं। साथ ही बिना पूर्व अनुमति किसी भी अधिकारी को अवकाश लेने या मुख्यालय छोड़ने पर सख्त मनाही रहेगी। धान खरीदी व्यवस्था की समीक्षा करते हुए उन्होंने बारदाना उपलब्धता, टोकन वितरण और खरीदी केन्द्रों की स्थिति की जानकारी ली तथा प्रक्रिया को सुचारू रखने के निर्देश दिए।

संबंधित नोडल अधिकारियों को निरंतर निगरानी और केन्द्रों के निरीक्षण करने को कहा गया। सड़क, बिजली-पानी के कार्यों सहित स्कूल, आंगनवाड़ी और अन्य शासकीय भवनों के निर्माण कार्यों में गुणवत्ता

सीईओ जिला पंचायत ने पीएम आवास निर्माण कार्य का किया निरीक्षण

गुणवत्ता, प्रगति और त्वरित क्रियान्वयन के निर्देश



Time: 2025-12-09 15:34
Note: avas samahar

बलौदाबाजार

सीईओ जिला पंचायत सुश्री दिव्या अग्रवाल मंगलवार को जनपद पंचायत कसडोल के वनांचल क्षेत्र स्थित ग्राम पंचायत सोनाखान में वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 के प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत नवीन आवासों का स्थल निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अप्रारंभ आवासों को जल्दी पूर्ण करने, गुणवत्तायुक्त आवास निर्माण, सामग्री उपलब्धता एवं कार्य में प्रगति लाने के निर्देश दिये। सुश्री अग्रवाल ने अप्रारंभ आवासों को तत्काल प्रारंभ

करने हेतु संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देशित किया ताकि सभी स्वीकृत आवासों को समय पर पूर्ण किया जा सके। उन्होंने कहा कि प्रत्येक निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण, पारदर्शी तथा निर्धारित समय सीमा में पूर्ण होना सुनिश्चित किया जाए। हितग्राहियों द्वारा बताई गई समस्याओं का समाधान करने निर्देशित किया। निरीक्षण के दौरान हितग्राही हरीश चौहान, मोहनदास मानिकपुरी एवं आशा चौहान के आवास प्रगतिरित पाए गए जिनमें तेजी लाने के लिए निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान जनपद सीईओ, जिला समन्वयक, विकासखण्ड समन्वयक एवं कार्यक्रम अधिकारी भी उपस्थित रहे।

अधिकारियों द्वारा कोषालयीन लिपिकीय कार्य डाटा एन्ट्री आपरेटरों से कराकर कोषालयीन लिपिकों के अधिकारों का हनन किया जा रहा- भानू पटेल

कोषालय अधिकारियों द्वारा वित्त विभाग के निर्देशों की उड़ाई जा रही ध्वजियां



केशकाल

छत्तीसगढ़ प्रदेश कोषालयीन शासकीय कर्मचारी संघ के संभागीय अध्यक्ष बस्तर भानू पटेल ने प्रेस विज्ञापित जारी कर कहा प्रदेश के कई कोषालय अधिकारियों द्वारा कोषालयीन लिपिकों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है जिससे कोषालयीन लिपिकों में रोष व्याप्त हो रहा है। इसके लिए संगठन द्वारा विशेष सचिव, वित्त विभाग एवं संचालक, कोष एवं लेखा को पत्र प्रेषित किया गया है जिससे जिला कोषालय रायपुर में डाटाएन्ट्री आपरेटर से लिपिकीय कार्य, इन्द्रावती कोषालय नया रायपुर में डाटाएन्ट्री आपरेटर को लिपिकीय कार्य, जिला कोषालय कवर्धा में डाटाएन्ट्री आपरेटर को लिपिकीय कार्य, जिला कोषालय जगदलपुर में डाटाएन्ट्री से लिपिकीय कार्य और भी प्रदेश अन्य कोषालयों में भी कराया जा रहा है साथ ही लिपिकों को उनके मुख्य कार्य से पृथक् कर कोषालय अधिकारियों एवं डाटाएन्ट्री आपरेटर मिल कर कोषालय का संचालन कर रहे हैं। जबकि डाटा एन्ट्री आपरेटरों को नियमों ज्ञान नहीं होता है न ही वे लेखा प्रशिक्षित होते हैं। वित्त विभाग के पत्र अनुसार लिपिकों का कार्य मुख्य रूप से नस्तिनों का प्रस्तुतीकरण, नस्तिनों का संधारण, रख रखाव, पत्राचार करना तथा

जिले की स्कूली व महाविद्यालयीन शिक्षा व्यवस्था उठाए कई गंभीर सवाल, सौपा झापन

अभावित कार्यकर्ताओं ने घेरा जिला कार्यालय, जिले के छात्रावासों में हों रहें अनैतिक कृत्यों पर लगाम लगाने की मांग



कवर्धा

कवर्धा विधायक तथा प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जहां एक तरफ जिले में संचालित शासकीय स्कूलों को स्मार्ट बनाने में जुटे हुए हैं वहीं दूसरी तरफ जिले की स्कूल शिक्षा व्यवस्था से लेकर महाविद्यालयी शिक्षा व्यवस्था को लेकर न सिर्फ विद्यार्थियों द्वारा बल्कि विभिन्न छात्र संगठनों द्वारा लगातार उंगली उठाई जा रही है। अभी सोमवार को ही इस बेहद गंभीर विषय को लेकर एनएसयुआई के कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने जिला मुख्यालय कवर्धा के पीजी कॉलेज में जोरदार प्रदर्शन करते हुए उप मुख्यमंत्री तथा कॉलेज प्रबंधन का पुतला फूँककर अपनी नौ सूत्रीय मांगों से संबंधित ज्ञापन प्रशासन को सौंपा था वहीं दूसरे दिन इसी विषय को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने जिला कार्यालय का घेराव किया और अपनी दस सूत्रीय मांगों को लेकर सीधे जिला कलेक्टर से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। अभावित के जिला संयोजक गजाधर वर्मा ने बताया कि जिले में स्कूल शिक्षा से लेकर महाविद्यालयीन शिक्षा संस्थान सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कहा कि अभी हाल ही में जिले के विकासखण्ड पंडरिया के अंतर्गत कुई छात्रावास में जिस प्रकार अधिकांशका द्वारा बालिका से अपने पति के कपड़े धुलाने के नाम पर मारपीट का मामला सामने आया है, आगरपानी छात्रावास के अंदर बालकों द्वारा जिस प्रकार खुलेआम धर्म्मपान करने की घटना सामने आई है वहीं जिला मुख्यालय कवर्धा में संचालित पीजी कॉलेज के कर्मचारी से मारपीट का मामला सामने आया है उसे देखकर सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है

जिले की स्कूली व महाविद्यालयीन शिक्षा व्यवस्था उठाए कई गंभीर सवाल, सौपा झापन

अभावित कार्यकर्ताओं ने घेरा जिला कार्यालय, जिले के छात्रावासों में हों रहें अनैतिक कृत्यों पर लगाम लगाने की मांग



कि जिले के शैक्षणिक संस्थानों की क्या स्थिति है। उन्होंने हैरानी जताते हुए है कि इस तरह के मामले लगातार सामने आने के बाद भी शासन-प्रशासन जिम्मेदारों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है जो चिंता का विषय है। अभावित के प्रदेश संयोजक तुलसी यादव ने कहा कि जिले की शैक्षणिक व्यवस्था चरमपरा गई है। अधिकार कर्मचारी अपने में मस्त हैं। व्यवस्था सुधार करने में किसी का ध्यान नहीं है। शिक्षक स्वयं नेताओं की तरह काम कर रहे हैं जिससे शैक्षणिक संस्थाओं की व्यवस्था गत में जा रही है।

उन्होंने कहा कि इन्हीं तमाम विषयों को लेकर आज अभावित ने जिला कार्यालय का घेराव कर अपनी दस सूत्रीय मांगों से संबंधित ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा है। ज्ञापन को सौंपने के दौरान मुख्य रूप से अभावित की सेवा कार्य संयोजक तुलसी यादव, जिला संयोजक गजाधर वर्मा, नगर मंत्री परमेश्वर साहू, हिरेंद्र बघेल, उदय तिवारी, महेंद्र, अजय साहू, गोपाल जायसवाल, अजय सहित बड़ी संख्या में अभावित के कार्यकर्ता व पदाधिकारी उपस्थित थे।

मांगों को लेकर शासन-प्रशासन के खिलाफ जमकर की गई नारेबाजी

अपनी दस सूत्रीय मांगों को लेकर हाथों में झंडा, बैनर लेकर जिला कार्यालय पहुंच अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिला कबीरधाम के सैकड़ों कार्यकर्ताओं द्वारा कार्यालय के सामने एकत्र होकर जमकर शासन-प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। बाद में कार्यकर्ता जिला कार्यालय का मुख्य द्वार लांघकर कार्यालय के भीतर घुस गए और यहां भी उन्होंने जमकर नारेबाजी की तथा धरने पर बैठ गए। जिसके बाद कलेक्टर ने अभावित के प्रतिनिधि मण्डल को मुलाकात के लिए बुलाया और उनसे मांगों व समस्याओं पर चर्चा की। अंततः कलेक्टर गोपाल वर्मा ने बातचीत कर

अंतरराष्ट्रीय ट्रेनर एवं मोटिवेशनल स्पीकर प्रोफेसर ईवी गिरीश (मुम्बई) का ब्रह्माकुमारी बघेरा आनंद सरोवर मे 21 से

आयोजित शिविर में प्रवेश निःशुल्क , रजिस्ट्रेशन आवश्यक

दुर्ग। भागती दौड़ती जिंदगी में हर पल खुशियों भरा, तनाव मुक्त कैसे हो,आंतरिक सशक्तिकरण के द्वारा चुनौतियों का सामना कैसे करें । इन सभी विषयों पर अपने अनूठे वक्तव्य से प्रशिक्षित करने अंतरराष्ट्रीय ट्रेनर एवं मोटिवेशनल स्पीकर प्रोफेसर ई.वी. गिरीश(मुम्बई) का प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्व विद्यालय के बघेरा स्थित आनंद सरोवर दुर्ग (छत्तीसगढ़) में आगमन हो रहा है।इस वर्ष के अंतिम माह में रविवार 21 दिसम्बर से 25 दिसंबर तक सुबह शाम प्रतिदिन दो सत्रों में सभी को संकल्प संबंध और कर्म में मधुरता लाने की कला सिखाने वाह जिंदगी वाह शिविर द्वारा जीवन को वाह वाह बनाने आ रहे हैं ताकि आने नया वर्ष 2027 खुशियों और उमंग से भरा,तनाव मुक्त हो । राजयोग ध्यान

विधियों का 30 वर्षों का अभ्यास, ईश्वर प्रदत्त बुद्धिमत्ता तथा आध्यात्मिकता से प्राप्त अंतर्दृष्टि, तीनों के अनूठे समन्वय से

अनेक आत्माओं को व्यक्तिगत एवं जीवन में सामंजस्य बनाकर बेहतर जीवन शैली अपनाने की कला सिखाने आपको महारत हासिल है ।

आपने देश के नामीग्रामी संस्थाओं जैसे इसरो,नाबार्ड,भारतीय सेना- इंस्टीटयुट स्टेट बैंक ऑफइंडिया, विभिन्न यूनिवर्सिटीज, आई.आई.एम.जैसे अनेक संस्थाओं में अलग-अलग विषयों पर व्याख्यान दिये हैं । प्रातः 8:00 से 9:00 एवं संध्या 7:00 से 8:00 दो सत्रों में आयोजित शिविर में प्रवेश पूर्णतः नि:शुल्क है किन्तु रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। सुबह-शाम दोनों में से किसी भी एक सत्र में इस शिविर में इसका लाभ लिया जा सकता है । शहर में कार्ड वितरित किया जा रहा है व मुख्य स्थलों पर होर्डिंस लगायी गयी है ।



टोकन का टेंशन : कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने कहा एक- दो दिन में समस्या दूर नहीं हुआ तो किसानों के साथ करेंगे चक्काजाम



पाटन। छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू हुई है, धान खरीदी प्रक्रिया को करीब 25 दिन होने को हैं, लेकिन दुर्ग जिले में किसान अब भी टोकन के टेंशन से परेशान हैं। सोमवार सुबह जिला कांग्रेस अध्यक्ष राकेश ठाकुर के फूँडा सोसायटी पहुँचने के खबर लगते ही किसान सैंकड़ो की संख्या में पहुँचकर कांग्रेस जिलाध्यक्ष राकेश ठाकुर से धान टोकन को लेकर अपनी समस्याएँ बताने लगे।

किसानों का कहना है कि सबसे बड़ी परेशानी टोकन की है, सुबह से ही केंद्रों में लंबी कतारों में खड़े हो जाते हैं, मगर न तो ऑनलाइन और न ही ऑफ़लाइन टोकन मिल पा रहा है, कई किसान बताते हैं कि वे पखवाड़े भर से चक्कर काट रहे हैं, लेकिन सिस्टम में टोकन स्लॉट

खुल ही नहीं रहा है। उपस्थित किसानों ने सोसायटी द्वारा जारी की जाने वाली 30 प्रतिशत धान का टोकन व्यक्ति विशेष को चिन्हार्कित कर दिए जाने का भी आरोप लगाया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष राकेश ठाकुर ने तत्काल मौके पर ही कलेक्टर दुर्ग अभिजीत सिंह से फोन पर चर्चा कर टोकन समस्या से अवगत कराया तथा टोकन लिमिट तत्काल बढ़ाने मांग किया। श्री ठाकुर ने अब तक धान उठाव के संबंध में शासन की निष्क्रियता पर भी चर्चा किया। कलेक्टर दुर्ग ने कांग्रेस जिलाध्यक्ष राकेश ठाकुर को आश्वासन दिया कि धान खरीदी में टोकन की लिमिट जल्द बढ़ाने आवश्यक कार्यवाही की जा रही है तथा धान उठाव के संबंध में शासन को पत्राचार भी कर रहे है।

पूरे मामले की जानकारी कांग्रेस जिलाध्यक्ष राकेश ठाकुर ने फ़ोन के माध्यम से एसडीएम पाटन लवकेश ध्रुव को भी दिया और कहा कि टोकन का समस्या एक या दो दिन में ठीक नहीं हुआ, लिमिट नहीं बढ़ाया गया तो कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ चक्काजाम करेगा जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। श्री ठाकुर ने राज्य की भाजपा सरकार के नियत में खोटे बताते हुवे धान नहीं खरीदने का षड्यंत्र बताया।

इस दौरान ब्लॉक अध्यक्ष महेंद्र वर्मा, जनपद सदस्य आनंद बघेल, दिना वर्मा, धनी वर्मा, डुमन वर्मा, विजय चिलक, सुंदर सैन, चेतन बंजारे, राजेश वर्मा, गोपाल ,गोकुल देशलहरा, हरीश ठाकुर, लोचन यादव, पालेश्वर ठाकुर, भोलेश्वर वर्मा, गिरधर साहू, हुलेश्वर पटेल, कैलाश साहू, ईश्वर चंद्राकर, दीपेश बंजारे, मिथलेश शर्मा, राजू शर्मा, सुरेंद्र वर्मा, जितेंद्र वर्मा, मनोज वर्मा, नारायण वर्मा, सुरेश चेलक, निखिल दास, नागेंद्र वर्मा, श्यामा मनहर, रेवा वर्मा, रीतकरण वर्मा, बोनू निर्माण, तुला राम निर्मल,भगवती साहू, मनोहर वर्मा सहित सैंकड़ो की संख्या में किसान मौजूद थे ।

कलेटर उड़के का धान खरीदी केंद्र परसुली का औचक निरीक्षण किया

गरियाबंद। खरीफविपणन वर्ष 2025-26 के लिए शासन के निर्देश पर 15 नवम्बर से जिले में धान खरीदी प्रारंभ है।कलेक्टर बीएस उड़के जिले में चल रहे धान उपार्जन केंद्रों का लगातार आकस्मिक निरीक्षण कर रहे है।कलेक्टर श्री उड़के ने आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित परसुली के धान उपार्जन केन्द्र का औचक निरीक्षण किया। जिसमें कुछ धान भरे बारदानों में 36.00 किलोग्राम वजन एवं अधिक सूखे हुए धान खरीदने की अनियमितता पाया गया।जिस पर कलेक्टर श्री उड़के ने धान खरीदी केन्द्र प्रभारी मुकेश कुमार यादव को पदीय दायित्वों के निर्वहन में गंभीर चुक एवं घोर लापरवाही के कारण तत्काल कार्य से मुक्त करने के निर्देश दिए है। उन्होंने स्पष्ट किया कि धान खरीदी में किसी भी प्रकार की अनियमितता, लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी।

मालवाहक वाहनों के लिए 10 तक होगा रोड डायवर्सन

बालोद। पुलिस अधीक्षक बालोद योगेश कुमार पटेल के निर्देशन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बालोद श्रीमति मोनिका ठाकुर के मार्गदर्शन में, देवांश सिंह राठौर अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) जिला बालोद एवं यातायात प्रभारी बालोद निरीक्षक रविशंकर पाण्डेय के नेतृत्व में जिले में विराट वीर मेला राजाराव पठार (कर्नेझर) में दिनांक 08 से 10 दिसंबर तक आयोजन में भीड़-भाड़ को देखते हुए बड़ी मालवाहक वाहनों के लिए परिवर्तित मार्ग (रोड डायवर्सन चार्ट) तैयार किया



गया है।

प्रतिवर्ष की भाँति इस वर्ष भी दिनांक 08, 09, एवं 10 दिसम्बर 2025 को शहीद वीर नारायण सिंह के शहादत दिवस के अवसर पर राजाराव पठार कर्नेझर राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 धमतरी से जगदलपुर मार्ग चारामा एवं धमतरी के मध्य जिला बालोद

अंतर्गत विराट वीर मेला राजाराव पठार (कर्नेझर) में आयोजन किया जाना है। जिसमें देव मेला आदिवासी हॉट, आदिवासी सांस्कृतिक कार्यक्रम, तथा शहीद वीरनाराण सिंह की श्रद्धांजली सभा का कार्यक्रम किया जाता है। जिसमें बालोद, धमतरी, कांकेर, राजनांदगांव, मानपुर मोहला क्षेत्र

के अदिवासी समाज के नागरिक, गणमान्य नागरिक, आम जनों का बड़ी संख्या में विराट वीर मेला राजाराव पठार में सम्मिलित होने के लिए आते है। इस मार्ग में यातायात व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए धमतरी से चारामा के मध्य तक बड़ी मालवाहक वाहनों के लिए प्रातः 08.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक प्रवेश निषेध किया गया है। इसके स्थान पर परिवर्तित मार्ग बनाया गया है जो इस प्रकार है- रायपुर/धमतरी तरफसे आने वाले बड़ी मालवाहक वाहन के लिए धमतरी सिहावा चौक से डायवर्ट होकर करेगाव-कोलियारी-नगरी-सिहावा-कांकेर होते हुए कोडागांव जगदलपुर से अपने

गतव्य स्थान की ओर जाएंगे तथा जगदलपुर कोडागांव की तरफसे आने वाले बड़ी मालवाहक वाहन केशकाल विश्रामपुरी चौक से- विश्रामपुरी-सिहावा-नगरी-धमतरी होते हुए रायपुर के लिए प्रस्थान करेंगे अथवा राजनांदगांव दुर्ग भिलाई जाने के लिए मांकड़ी चौक से भानुप्रतापुर-डौण्डी-दल्लीराजहरा-राजनांदगांव-होते हुए दुर्ग भिलाई रायपुर जाएंगे।

बालोद पुलिस वाहन चालकों एवं वाहन मालिकों से अपील करता है की वाहन चालक परिवर्तित मार्ग का उपयोग करे एवं यातायात व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन हेतु बालोद पुलिस का सहयोग करें।

धान खरीदी केन्द्रों में किसानो की समस्या पर जमकर हंगामा !

रानीतराई धान खरीदी केंद्र में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष धेराव में पहुंचे

रानीतराई। ब्लाक कांग्रेस कमेटी जामगांव आर के तत्वावधान में धान खरीदी केंद्र में भाजपा सरकार की गलत नीतियों के कारण किसानों को धान बेचने में भारी दिक्कत हो रही है। जिला कांग्रेस के निर्देश में सोमवार को डिंडाभाटा धान खरीदी केंद्र में किसानों व कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी व हंगामे हुई।जिला अध्यक्ष राकेश ठाकुर ने समिति प्रबन्धक वर्मा व नायब सहसीलदार को दो दिन में धान खरीदी व्यवस्था में सुधार नहीं किया तो पाटन के सभी



समितियो मे चक्काजाम व उग्र आंदोलन करेंगे। शांतिपूर्वक किसानों ने जिला कलेक्टर एवं कृषि मंत्री के नाम पर ज्ञापन पाटन नायब तहसीलदार भूपेंद्र सिंह को सौंपा गया।वर्ष 2025-26 में धान खरीदी व्यवस्था में गंभीर अनियमितताएँ एवं अव्यवस्थाएँ पाटन ब्लॉक के अधीनस्थ धान खरीदी केन्द्रों में विभिन्न समस्या सहित आई है जिसमे ऑनलाइन व ऑफलाइन टोकन वितरण में व्यापक समस्या,किसानों को

समय पर टोकन प्राप्त न होने से आर्थिक नुकसान और भीडभाड की स्थिति,धान खरीदी लिमिट में सरलीकरण,धान विक्रय हेतु पंजीयन में परेशानी का निराकरण,केन्द्रों में प्रतिदिन का खरीदी लिमिट को बढ़ाने,तत्काल परिवहन व्यवस्था चालू करने की मांग रखी गई। विधायक प्रतिनिधि अशोक साहू ने अन्नदाता किसानो की परेशानी से दूर सरकार चिरनिद्रा में सोई हुई है।आज छत्तीसगढ़ से सभी

किसान हताश,निराश हो गए हैं। राकेश ठाकुर जिलाध्यक्ष, राजेश ठाकुर ब्लाक कांग्रेस कमेटी,अशोक साहू विधायक प्रतिनिधि, महेंद्र वर्मा,उमाकांत चन्द्रकर , विष्णु चन्द्रकर,लुल्ली चक्रधारी,सोहन जोशी,भूपेंद्र बघेल,कपूर साहू,देव कुमार निषाद,रश्मि भेद प्रकाश वर्मा जनपद सदस्य,भविष्य कुमार जैन,यादव राम सेन,भजन रघुवंशी,सत्यनारायण टिकरिहा सरपंच, आनंद बघेल जनपद सदस्य, जानकी चोपड़िया सरपंच, द्रौपदी साहू, कमलेश ठाकुर,निखिल साहू, दुकालू राम निषाद,पालेश्वर ठाकुर, हरीश ठाकुर,हेमू भानुाराम वर्मा डोमन चंद्राकर डोमन साहू नारद साहू राम सिंह आगरे रामा साहू विष्णु वर्मा सहित किसान उपस्थित थे।

स्वर्गवासी शिक्षक के साथ बस्तर में पदस्थ शिक्षिका को प्रशिक्षण में उपस्थित होने का बीआरसी का फरमान

गरियाबंद। जिले के छुरा विकास खण्ड में ऐसे अनुभवहीन कर्मचारी को विभाग प्रमुख बनाया गया है कि अधिनस्थ कर्मचारी के साथ साथ स्वर्गवासी कर्मचारी,तबादला में अन्यत्र पदस्थ कर्मचारी के परिजन एवं मेडिकल अवकाश में रहने वाले कर्मचारी के साथ साथ परिवार को नोटिस जारी कर मुफ्त में मानसिक परेशानी झेलनी पड़ी रही है। जनपद पंचायत प्रभारी सीईओ सतीष चन्द्रवंशी हो या खण्ड स्रोत समन्वयक समग्र शिक्षा अधिकारी छुरा।

छुरा खण्ड स्रोत समन्वयक समग्र शिक्षा विभाग छुरा ने आंख बंद कर विकास खण्ड स्तर पर कक्षा छठवीं के नवीन पाठ्यक्रमों पर शिक्षकों का प्रशिक्षण के लिए छुरा विकास खण्ड के नब्बे शिक्षकों को पांच दिवसीय प्रशिक्षण में उपस्थित रहने का फरमान जारी किया गया है,प्रशिक्षण ब्लाक मुख्यालय में आयोजित नहीं कर बीआरसी मार्कण्डेय अपने गृह ग्राम लोहझर के हाईस्कूल में रखा है,ब्लाक मुख्यालय में सभी प्रकार से सुविधाएं उपलब्ध होने के बावजूद लोहझर गांव में आयोजित करना समझ से परे है,बीआरसी के पास इसका कोई ठोस जवाब नहीं है ।

पांच दिवसीय प्रशिक्षण में सरकंडा स्कूल में पदस्थ शिक्षक स्वर्गीय नीलकंठ साहू जिसका निधन 24 सितम्बर 2024 को ? हो गया था,स्वर्गीय नीलकंठ साहू को प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए आदेश जारी किया गया है।इसी तरह श्रीमती अनिता रवि शिक्षिका हलबाकोटा विकास खण्ड जगदलपुर बस्तर को प्रशिक्षण में उपस्थित रहने,एवं एम एल तारक पूर्व माध्यमिक शाला पाण्डुका जो मेडिकल अवकाश पर जिसे पांच दिवसीय प्रशिक्षण में उपस्थित होकर प्रशिक्षण प्राप्त करने का आदेश दिया गया।



विधायक डॉ. सम्पत अग्रवाल ने आगे कहा कि यह 15.8 किमी. लंबा मार्ग सांकरा को परसवानी से जोड़ते हुए आसपास के कई गांवों के लिए मुख्य कनेक्टिविटी प्रदान करता है। इस मार्ग के उन्नयन से क्षेत्र में व्यापार, कृषि गतिविधियों और सामान्य जनजीवन में सकारात्मक बदलाव आने की उम्मीद है। विधायक डॉ. सम्पत अग्रवाल ने कहा कि वह सुनिश्चित करेंगे कि इस मार्ग का निर्माण कार्य उच्च गुणवत्ता और निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा हो।

सम्पत अग्रवाल ने आगे कहा कि यह 15.8 किमी. लंबा मार्ग सांकरा को परसवानी से जोड़ते हुए आसपास के कई गांवों के लिए मुख्य कनेक्टिविटी प्रदान करता है। इस मार्ग के उन्नयन से क्षेत्र में व्यापार, कृषि गतिविधियों और सामान्य जनजीवन में सकारात्मक बदलाव आने की उम्मीद है। विधायक डॉ. सम्पत अग्रवाल ने कहा कि वह सुनिश्चित करेंगे कि इस मार्ग का निर्माण कार्य उच्च गुणवत्ता और निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा हो।

क्षेत्र के विकास के प्रति कटिबद्धता का प्रमाण

विधायक डॉ. सम्पत अग्रवाल के सतत प्रयासों से सांकरा से परसवानी रोड के लिए मिली28 करोड़ की मंजूरी

पिथौरा। बसना विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक डॉ. सम्पत अग्रवाल के अथक प्रयासों से क्षेत्र को एक बड़ी सौगात मिली है। राज्य सरकार ने सांकरा से परसवानी तक 15.8 किलोमीटर लंबे महत्वपूर्ण सड़क मार्ग के निर्माण और उन्नयन के लिए 28 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस महत्वपूर्ण स्वीकृति के साथ, लंबे समय से जर्जर स्थिति में रहे इस मार्ग के पुनर्निर्माण का रास्ता साफ हो गया है,

जिससे क्षेत्र के हजारों ग्रामीणों को सुगम और सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिल सकेगी।

राज्य सरकार द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त होने पर बसना विधायक डॉ. सम्पत अग्रवाल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय,उपमुख्यमंत्री अरुण साव और वित्त मंत्री ओ पी चौधरी का हृदय से आभार व्यक्त किया। विधायक डॉ. सम्पत अग्रवाल ने कहा कि सांकरा से परसवानी मार्ग की स्वीकृति बसना विधानसभा क्षेत्र के निवासियों की वर्षों पुरानी और अत्यंत महत्वपूर्ण मांग थी। यह केवल एक सड़क नहीं है, बल्कि इस क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास की जीवन्मरेखा है। उन्होंने जोर दिया कि बेहतर सड़कों से न केवल आवागमन

आसान होता है, बल्कि किसानों को अपनी उपज मंडियों तक ले जाने में सुविधा मिलती है और शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित होती है। विधायक डॉ. सम्पत अग्रवाल ने आगे कहा कि यह मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उपमुख्यमंत्री अरुण साव और वित्त मंत्री ओ पी चौधरी का आभारी हूँ, जिन्होंने बसना क्षेत्र के विकास के प्रति मेरी अपील को गंभीरता से लिया और प्राथमिकता के आधार पर इस 28 करोड़ रुपये की राशि को स्वीकृत किया। यह स्वीकृति राज्य सरकार की 'सबका साथ, सबका विकास' की भावना और क्षेत्र के त्वरित विकास के प्रति उनकी कटिबद्धता को दर्शाती है। विधायक डॉ



मोबाइल की जांच में ऑनलाइन सट्टा ऐप और सट्टेबाजी के साक्ष्य मिलने पर पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें टीमक ने अपने दोस्त पवन तम्बूले का नाम बताया। उसके अनुरार पवन तम्बूले ने ही उसे आईडी और पासवर्ड बनाकर उपलब्ध कराया था, जिसके जरिए ऑनलाइन सट्टा लगाया जा रहा था।

घटना के बाद मुख्य आरोपी पवन

तम्बूले फ्फार हो गया था। पुलिस टीम ने उसके संभावित ठिकानों पर दबिश दी और अंततः उसे शंकर नगर मुक्तिधाम के पास से पकड़ा। आरोपी के पास से दो मोबाइल बरामद किए गए, जिनमें सट्टेबाजी से जुड़े तकनीकी साक्ष्य पाए गए। दोनों आरोपियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर पुलिस ने आगे की विवेचना शुरू की है। पुलिसांव पुलिस ने ऑनलाइन सट्टेबाजी में संलिप्त अन्य संभावित व्यक्तियों की भी तलाश शुरू कर दी है।

ऑनलाइन सट्टा प्रकरण में पुलगांव पुलिस की बड़ी कार्रवाई, फरार आरोपी पवन तम्बूले गिरफ्तार

दुर्ग, 09 दिसंबर (आरएनएस)। पुलगांव पुलिस ने ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा मामले में कार्रवाई करते हुए फ्फार आरोपी पवन तम्बूले (उम्र 26 वर्ष, निवासी शंकर नगर) को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया है। आरोपी के कब्जे से दो मोबाइल फ़ोन जप्त किए गए हैं। इससे पहले इस केस में एक अन्य आरोपी टीमक बंजारे को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

कैसे फैला सट्टेबाजी का जाल

दिनांक 03 दिसंबर 2025 को पुलिस को मुखर्बिबर से सूचना मिली थी कि पुलगांव चौक के पास टीमक बंजारे नामक युवक अपने मोबाइल से ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा खेल रहा है। सूचना पर पुलिस टीम ने घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ा। पूछताछ में उसने बताया कि वह अपने मोबाइल पर इंडिया बनाम साउथ अफ्रीका मैच में हार-जीत पर पैसे का दांव लगा रहा था।

संक्षिप्त-खबर

मनरेगा से बना तालाब, बना आत्मनिर्भरता की मिसाल, ग्रामीण किसान की बदल गई किस्मत, आय में हुई कई गुना वृद्धि



दुर्ग। महात्मा गांधी नरेगा योजना ने एक बार फिर ग्रामीणों के जीवन में बदलाव लाया। ग्राम पंचायत महमरा में मनरेगा के तहत निर्मित निजी तालाब (डबरी) ने किसान मूलचंद निषाद और उनके परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार लाया है। लगभग 6 किमी दूर स्थित इस गांव में रहने वाला 4 सदस्यीय परिवार पहले केवल द्विपसलीय खेती पर निर्भर था, जिससे आय सीमित थी और जीवनयापन चुनौतीपूर्ण बना रहता था। लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। मनरेगा से बने इस तालाब ने मूलचंद निषाद के जीवन में नई रोशनी लेकर आयी। तालाब को उन्होंने दो हिस्सों में विकसित किया। पहले हिस्से में मछली पालन और दूसरे हिस्से में ढेस कांदा उत्पादन। इतना ही नहीं तालाब की मेड़ पर उन्होंने मौसमी सब्जियों की खेती भी शुरू की, जिससे नियमित आय का स्रोत बन गया है।

सब्जी उत्पादन से उन्हें प्रतिमाह लगभग 10 हजार से 12 हजार की आय हो रही है। मछली पालन ने उनकी वार्षिक आय में और अधिक इजाफ़ करते हुए हर वर्ष लगभग ढेड लाख तक की आमदनी प्राप्त कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, परिवार द्वारा किए जा रहे मूली पालन से भी अतिरिक्त आय अर्जित कर रहे हैं। एक किसान के लिए यह आय उनके परिवार को आर्थिक सुरक्षा भी प्रदान कर रही है। बारिश का पानी सीधे तालाब में संग्रहित होने से उनके खेतों को भरपूर सिंचाई मिलने लगी। अब वे टमाटर, मिर्च, धनिया और अन्य सब्जियों की अतिरिक्त फसल लेकर बाजार में बेच पा रहे हैं। इस निर्माण कार्य से मनरेगा के तहत ग्रामीण परिवारों को भी अच्छा रोजगार मिला। आज यह डबरी न सिर्फ जल संरक्षण का साधन है, बल्कि ग्रामीण परिवार की आजीविका का माध्यम भी है।

ग्रीष्म ऋतु से पहले कलेक्टर की अपील जल संरक्षण को दें प्राथमिकता

गरियाबंद। कलेक्टर बी.एस.उड़के ने आगामी ग्रीष्म ऋतु को ध्यान में रखते हुए जिले के सभी नागरिकों एवं कृषक भाइयों-बहनों से पेयजल संरक्षण तथा जल के समुचित उपयोग के लिए अपील की है। उन्होंने कहा कि गर्मी के मौसम में भू-जल स्तर स्वाभाविक रूप से नीचे चला जाता है,जिसके कारण पेयजल उपलब्धता पर दबाव बढ़ जाता है।ऐसी स्थिति में प्रत्येक नागरिक का दायित्व है कि वह जल का समुचित उपयोग करें और अनावश्यक जल की बर्बादी से बचे।कलेक्टर श्री उड़के ने कृषकों से विशेष आग्रह करते हुए कहा कि जिले में इस वर्ष ग्रीष्मकालीन धान की फसल के लिए जलाशयों से सिंचाई हेतु पानी की आपूर्ति उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। इसलिए किसान अत्यधिक जल उपयोग वाली धान की फसल लेने से परहेज करें।

उन्होंने कहा कि धान की खेती में अत्यधिक मात्रा में पानी लगता है,जिसके कारण गर्मी के समय जलसंकट और अधिक गंभीर रूप से बढ़ सकता है। उन्होंने किसानों को सलाह दी कि इस वर्ष धान की जगह कम जल उपयोग वाली फसलें जैसे तिल, मूंग, उड़द, मसूर,अरहर,कोदो-कुटकी,मक्का आदि वैकल्पिक फसलें अपनाएँ। ये फसलें न केवल जल संरक्षण में सहायक होंगी बल्कि किसानों को बेहतर नगदी आय का अवसर भी प्रदान करेंगी।उन्होंने कहा कि शासन एवं जिला प्रशासन द्वारा नगदी, दलहनी एवं तिलहनी फसलों के प्रचार-प्रसार, गुणवत्तायुक्त बीज उपलब्धता और तकनीकी मार्गदर्शन के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। किसान इन वैकल्पिक फसलों की ओर बढ़ते हैं, तो न केवल जल व्यय कम होगा,बल्कि मिट्टी की उर्वरता भी संरक्षित रहेगी और किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी।उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रशासनिक प्रयास तभी सफ़्त होंगे जब नागरिक स्वयं जल संरक्षण की आदत को अपनाएँ। उन्होंने आम नागरिकों से अपील की है कि जलस्रोतों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करें,नलों और पाइपों से पानी की रिसाव रोकें,घरों में वर्षा जल संचयन की व्यवस्था विकसित करें,और समुदाय के स्तर पर जल संरक्षण के कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाएँ। उन्होंने कहा कि जल बचाना सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं,बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित रखने का संकल्प है।कलेक्टर ने जनप्रतिनिधियों,गणमान्य नागरिकों,किसान भाइयों तथा जिलेवासियों से पूर्ण सहयोग करने अपील की।

विधायक ललित चंद्राकर ने श्रीमद भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ में सम्मिलित हुए

दुर्ग। दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर अपने धर्मपत्नी मीनाक्षी चंद्राकर के साथ दुर्ग मोहन नगर पांडे टिम्बर में आयोजित श्रीमद भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने व्यास पीठ की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त किया और कथा श्रवण कर आध्यात्मिक लाभ प्राप्त किया।और प्रदेश वासियों की खुशहाली की कामना किया। विधायक ललित चंद्राकर ने कहा कि श्रीमद भागवत गीता हमें जीवन के सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। उन्होंने कहा कि भगवान की भक्ति और सेवा में ही जीवन की सच्ची शांति और सुख है। इस अवसर पर गुड्डू पांडे, सुशीला पांडे सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु जन उपस्थित रहे। सभी ने विधायक ललित चंद्राकर और उनकी धर्मपत्नी मीनाक्षी चंद्राकर का स्वागत किया।